भारत ई. टी. सी. के लिए अटॉर्नी जनरल। ईटीसी।

क.

वी.

अमरताल प्रजीवंदास और ओ. आर. एस.ईटीसी। ईटीसी।

12 मई, 1994

[ए. एम. अहमदी, पी. बी. सावंत, के. रामास्वामी, के. जयचंद्र रेड्डी, एस. सी. अग्रवाल, एस. मोहन,

बी. पी. जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जी. एन. रे और एन. वेंकटचाला, जे. जे.]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 22 (4) से (7), अनुसूची VII और IX, s

प्रविष्टि 3 सूची 3-विदेशी मुद्रा संरक्षण और स्मग ग्लिंग गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974-तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976-क्या समान दायित्व कोफेपोसा और सेफेमा को लागू करने के लिए सक्षम है-की संवैधानिक वैधता-आयोजित, हाँ-दोनों अधिनियमों को IX अनुसूची में रखा गया है, उन्हें D.

अनुच्छेद 31 (बी)।विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी की रोकथाम

नागरिक अधिनियम, 1974-धारा 12 ए के साथ पठित धारा 3-आपातकाल की अवधि के दौरान बनाई गई धारा 12 ए के साथ पठित धारा 3 के तहत निरोध का आदेश-क्या तस्करों और ई की धारा 6 के तहत कार्रवाई करने के लिए आधार बन सकता है।

विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976-आयोजित, हाँ क्या हिरासत के ऐसे आदेश की वैधता को चुनौती दी जाएगी जब SAFEMA के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है, भले ही कहा गया आदेश लागू होना बंद हो गया हो और इसके संचालन के दौरान चुनौती नहीं दी गई हो-आयोजित, नहीं-आदेश की वैधता का परीक्षण उस समय प्राप्त कानून की स्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए जब आदेश दिया गया था और संचालन की अवधि के दौरान।एफ तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976-धारा 3 (1) (सी)-अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां-वैधता की परिभाषा-क्या "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" की परिभाषा निरोध के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है-आयोजित, सं।

जी.

तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976-धारा 2 (2) (ए) और (बी)-धारा 2 (2) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आने वाली किसी व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की ज़ब्ती क्या बंदियों के रिश्तेदारों और सहयोगियों पर अधिनियम का आवेदन उल्लंघन है

एच.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,19 और 21-आयोजित, सं।

1 2

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974-धारा 5-ए-की वैधता-क्या धारा 5-ए भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड (5) का उल्लंघन करती है-सं. भारत का संविधान-अनुच्छेद 22 (5)-भारत का संविधान की धारा 5-ए की वैधता

कोफेपोसा-क्या धारा 5-ए अनुच्छेद 22 (5) का उल्लंघन करती है।

वर्ष 1976 में आपातकाल की अवधि के दौरान, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 की धारा 3 के तहत हिरासत के कई आदेश दिए गए थे।धारा 12-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, बंदियों को न तो निरोध के आधार प्रदान किए गए थे और न ही उनके मामलों को सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था।अनुच्छेद 359 (1) के तहत आदेश और के संचालन के कारण

आई.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 358 के अनुसार, उनके पास कोई उपाय नहीं था और वे राहत के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकते थे।आपातकाल हटाए जाने पर बंदियों को रिहा कर दिया गया।तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 की धारा 6 डी के तहत उन बंदियों, उनके रिश्तेदारों और समाजसेवियों को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें उनसे कारण दिखाने के लिए कहा गया था कि नोटिस में उल्लिखित संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के रूप में घोषित और ज़ब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए।आपातकाल के दौरान कोफेपोसा के तहत हिरासत में लिए गए लोगों को हिरासत में लेने के आदेश कार्रवाई की नींव थे

ई उनके खिलाफ सेफेमा के तहत।बंदियों ने कोफेपोसा, सेफेमा की संवैधानिक वैधता और भारत के संविधान के 39 वें, 40 वें और 42 वें संशोधन को चुनौती देते हुए उक्त नोटिसों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालयों में रिट याचिकाएं दायर कीं, जिसमें कोफेपोसा और सेफेमा को 9 वीं अनुसूची में रखा गया है।विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाओं को उसमें उठाए गए महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

यद्यपि 39 वीं, 40 वीं और 40 वीं की संवैधानिक वैधता को चुनौती

42 और संविधान में संशोधन रिट याचिकाओं में इस आधार पर किए गए थे कि उक्त संशोधन संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।

जी.

संविधान, यह स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि उक्त संशोधन अधिनियमों ने किस तरह से प्राधिकरण का उल्लंघन किया।याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि

सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 की प्रविष्टि 9 से उतना संबंधित नहीं था जितना कि निवारक निरोध प्रदान किया गया था।

:

इसके लिए रक्षा, विदेशी मामलों से जुड़े कारणों से नहीं था या

एच भारत की सुरक्षा।यहां तक कि सूची III की प्रविष्टि 3 भी, जो प्रस्तुत की गई थी, वारंट नहीं थी

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास

3

उक्त अधिनियम।जहाँ तक सेफेमा का संबंध है, यह तर्क दिया गया था कि यह ए सूची I या सूची III में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि चूंकि कोफेपोसा के तहत हिरासत के आदेश को हिरासत में लिए गए लोगों, उनके रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों के खिलाफ सेफेमा के तहत कार्रवाई का आधार बनाया गया था, इसलिए वे हिरासत के आदेश की वैधता का बदला लेने के हकदार थे।उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 359 (1) के तहत दिए गए आदेश के आधार पर, अनुच्छेद 14,21 और 22 द्वारा उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया गया था, बल्कि केवल उनके प्रवर्तन के लिए कदम उठाने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया था।उनके खिलाफ दिया गया निरोध आदेश अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) के उल्लंघन के लिए अमान्य और अवैध था और इसलिए, सी सेफेमा के तहत कार्रवाई के आधार के रूप में काम नहीं कर सकता था। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि निरोध आदेश शासित हैं

कोफेपोसा की धारा 12-ए स्वाभाविक रूप से मनमाना और अन्यायपूर्ण थी।याचिकाकर्ताओं ने तब अवैध रूप से अर्जित की गई परिभाषा पर हमला किया

अनुचितता, मनमानेपन या अनुच्छेद 14,19 और 21 के उल्लंघन के आधार पर सेफेमा की धारा 3 (1) के खंड (सी) में गुण।डी वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया गया था कि यदि उक्त परिभाषा IX अनुसूची में शामिल होने के कारण अनुपलब्ध थी, तो परिभाषा को पढ़ा जाना चाहिए ताकि इसे केवल SAFEMA की धारा 2 (9) में उल्लिखित अधिनियमों में निहित निषेधों का उल्लंघन करके अर्जित संपत्तियों तक ही सीमित किया जा सके।यह तर्क दिया गया कि सेफेमा के प्रावधानों का विस्तार ई तक किया गया है

रिश्तेदार, सहयोगी और अन्य धारक अत्यधिक नियमन का मामला था।यह इंगित किया गया था कि स्पष्टीकरण (2) में 'रिश्तेदार' और स्पष्टीकरण (3) में 'सहयोगी' की परिभाषाएँ इतनी व्यापक थीं कि दोषी/बंदी के साथ दूर से संबंधित या उससे जुड़े व्यक्ति को भी जाल के भीतर लाया जा सकता था।

}

सेफेमा से।

च

याचिकाकर्ताओं ने धारा 5-ए की वैधता को भी चुनौती दी।

कोफेपोसा इस आधार पर कि यह प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करता है

अनुच्छेद 22 के खंड (5) द्वारा।

अनुच्छेद 359 के खंड (1 ए) के प्रावधानों पर आधारित, यह था जी

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा प्रस्तुत किया गया कि

एस. ए. एफ. ई. एम. ए. की धारा 6 के तहत नोटिस जारी करने की तारीख को प्राप्त करने वाले कानून के संदर्भ में निरोध आदेशों का निर्णय लिया जाना था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 359 के खंड (1 ए) ने ऐसे सभी आदेशों को सुरक्षित रखा है।यह कहा गया था कि उपचार का निलंबन स्वयं अधिकार का निलंबन था और उनके अनुसार, अनुच्छेद 358 और एक आदेश एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी. पी. के बीच कोई अंतर नहीं था।

1 अनुच्छेद 359 (1) के तहत एस. सी. आर. ए.यह तर्क दिया गया था कि आपातकाल के दौरान पारित निरोध आदेश जिस पर कोफेपोसा की धारा 12-ए लागू होती है, हो सकता है

शुरू में शून्य या गैर-पूर्व नहीं कहा जा सकता है।जब आदेश दिए गए तो वे अच्छे और वैध थे, हालाँकि राष्ट्रपति के आदेश की समाप्ति के साथ उनका संचालन बंद हो गया।निर्धारण के लिए उठाए गए प्रश्न थेःख (1) क्या संसद कोफेपोसा और सेफेमा को लागू करने के लिए सक्षम नहीं थी?

(2) क्या आपातकाल की अवधि के दौरान कोफेपोसा की धारा 12-ए के साथ पठित धारा 3 के तहत निरोध का आदेश घोषित किया गया है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के तहत-अनुच्छेद 19 के परिणामी 'निलंबन' के साथ और किस अवधि के दौरान अनुच्छेद 14,21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत का रुख करने का अधिकार निलंबित कर दिया गया था-फाउंडेशन से बंदी, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ SAFEMA की धारा 6 के तहत कार्रवाई करने के लिए?और यदि ऐसा होता है, तो क्या निरोध के ऐसे आदेश की वैधता को हिरासत में लिए गए डी और/या उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों द्वारा चुनौती दी जा सकती है, जब उनके खिलाफ SAFEMA के तहत कार्यवाही की जाती है, भले ही निरोध के उक्त आदेश को लागू करना बंद कर दिया गया हो और या तो चुनौती नहीं दी गई थी-या इसके संचालन के दौरान सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी गई थी?

(3) यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या

ई.

निरोध के आदेश की वैधता का परीक्षण उक्त आदेश देने के समय और उसके संचालन की अवधि के दौरान प्राप्त कानून की स्थिति के संदर्भ में या SAFEMA की धारा 6 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख को प्राप्त कानून की स्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

च

(4) क्या खंड में "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" की परिभाषा

(सेफेमा की धारा 3 (1) का ग) अनुच्छेद 14,19 और 21 द्वारा गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्या संविधान की नौवीं अनुसूची में सेफेमा का समावेश इस तरह के उल्लंघन, यदि कोई हो, को ठीक करता है?!

जी.

(5) क्या रिश्तेदारों के लिए सेफेमा का आवेदन और के रूप में

बंदियों का समाज अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन करता है?क्या उक्त अधिनियम को नौवीं अनुसूची में शामिल करने से इस तरह के उल्लंघन, यदि कोई हो, को ठीक किया जा सकता है।(6) क्या कोफेपोसा की धारा 5-ए एच अनुच्छेद 22 के खंड (5) का उल्लंघन है?

1

5

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास

इस मामले का निपटारा करते हुए, यह न्यायालय

क.

अवधारित 1.1 .संसद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 और तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 दोनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी।कोफेपोसा सूची बी III की प्रविष्टि 3 से संबंधित है क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा से जुड़े कारणों के साथ-साथ समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए निवारक निरोध का प्रावधान करता है।[22 - एच, 23-ए, 53-सी] भारत संघ बनाम।एच. ई. एस. ढिल्लन, [1972] 2 एस. सी. आर. 33, पर भरोसा किया।एस 1.2।कोफेपोसा को संविधान 39 वें (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा नौवीं अनुसूची में रखा गया था, जबकि सेफेमा और कोफेपोसा को

(संशोधन) अधिनियम, 1976 को संविधान 40 वें (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा नौवीं अनुसूची में रखा गया था।दोनों अधिनियमों को IX अनुसूची में रखा गया है, वे अनुच्छेद 31 (बी) द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा का आनंद लेते हैं।याचिकाकर्ता अपनी इस दलील को कायम नहीं रख पाए हैं कि 39 वां डी (संशोधन) अधिनियम और 40 वां (संशोधन) अधिनियम, जो उक्त अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में रखते हैं, असंवैधानिक थे, उन्हें अच्छा और वैध माना जाता है।[11 - डी, 21-सी]

1.3 .कोफेपोसा, ई की धारा 3 के तहत किया गया निरोध का आदेश

जो इसकी धारा 12-ए द्वारा शासित थी, अभी भी सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के उद्देश्य के लिए और उसके अर्थ के भीतर निरोध का आदेश है।चूँकि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 14,21 और 22 को निलंबित करने वाले अनुच्छेद 359 (1) के तहत एक आदेश जारी किया था, इसलिए यह संसद के लिए अनुच्छेद 359 के खंड (1 ए) के आधार पर कोफेपोसा की धारा 12-ए को उस अवधि के लिए अधिनियमित करने के लिए सक्षम हो गया, जिसके लिए राष्ट्रपति का आदेश एफ लागू था।इसका उद्देश्य आपातकाल के उद्देश्यों को प्राप्त करना था।एक बार जब धारा 12-ए को कानून का एक सक्षम टुकड़ा माना जाता है, तो उसके तहत किए गए निरोध के आदेश (यानी निरोध के आदेश जिन पर उक्त प्रावधान लागू होता है) को सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के उद्देश्य के लिए और उसके अर्थ के भीतर निरोध के आदेशों के बराबर नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से जी

धारा 2 (2) (बी) की स्पष्ट भाषा का दृष्टिकोण (जिसमें परंतुक (iii) भी शामिल है)-और संविधान की नौवीं अनुसूची में उनके समावेश के आधार पर दोनों अधिनियमों द्वारा प्राप्त संरक्षण।[53 - ई-जी] 1.4।निरोध का एक आदेश जिस पर धारा 12-ए लागू होती है और साथ ही निरोध का एक आदेश जिस पर धारा 12-ए लागू नहीं थी, एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] एस. पी. पी. की सेवा कर सकता है।

1 एस सी आर।

6

ए, आधार के रूप में, ऐसे बंदी और उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के लिए सेफेमा को लागू करने के लिए, बशर्ते कि निरोध का ऐसा आदेश धारा 2 (2) (बी) के परंतुक में किसी भी उपखंड को आकर्षित नहीं करता है।यदि ऐसे बंदी ने उस अवधि के दौरान अदालत के समक्ष उक्त निरोध (या तो स्वयं या अपने अगले मित्र के माध्यम से) पर सवाल उठाने का विकल्प नहीं चुना जब निरोध का ऐसा आदेश लागू था, या उस पर हमला करने में असफल रहा-वह, या

उसके रिश्तेदार और सहयोगी इसकी वैधता पर हमला या सवाल नहीं उठा सकते हैं जब इसे उसके लिए या उसके रिश्तेदारों या सहयोगियों के लिए SAFEMA लागू करने का आधार बनाया जाता है।[53 - एच, 54-ए-बी] यह इस कारण से है कि भले ही उसे उक्त आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी जाती है जब उसे सेफेमा की धारा 6 के तहत नोटिस दिया जाता है,

एस.

चुनौती की जांच कानून की स्थिति के संदर्भ में की जानी चाहिए जैसा कि उक्त आदेश दिए जाने के समय प्राप्त किया गया था और जिस अवधि के दौरान निरोध का उक्त आदेश लागू था, उस अवधि के दौरान लागू कानून।[40 - डी] भारत संघ, v.हाजी मस्तान मिर्जा, [1984] 3 एस. सी. आर. 1, ने खारिज कर दिया।

डी.

भारत संघ बनाम।मनोहर लाल नारंग, [1987] 2 एस. सी. सी. 241, डिस्टिन गैश्ड।

1.5 .सेफेमा की धारा 3 के खंड (सी) में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की परिभाषा अमान्य या अप्रभावी नहीं है।परिभाषा काफी व्यापक ई है।यह न केवल अधिनियम के बाद अर्जित संपत्ति को लेता है, बल्कि अधिनियम से पहले अर्जित संपत्ति को भी लेता है, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो।यह ऐसी संपत्ति लेता है जो अवैध गतिविधि से आंशिक रूप से अर्जित की गई हो सकती है।[40 - एफ-जी]

दोनों अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में रखा गया है और वे

च

अनुच्छेद 31 (बी) द्वारा प्रदत्त प्रतिरक्षा और इसलिए, अनुचित, मनमानेपन या भाग-III से संबंधित किसी भी आधार के आधार पर उक्त परिभाषा की वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती है।इसके अलावा, धारा 3 के खंड (सी) में प्रयुक्त स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा को देखते हुए, पढ़ने के साधन का सहारा लेने की अनुमति नहीं है।इसलिए, न तो जी की उक्त परिभाषा की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है और न ही खंड में स्पष्ट और असंदिग्ध शब्दों को पढ़ने के लिए कोई वारंट है, जब इस तरह के प्रावधान का औचित्य पर्याप्त और अधिक है।[41 - डी-एच एंड 42-ए-डी] हांगकांग के लिए अटॉर्नी जनरल बनाम।रीड, [1993] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1143, ने भरोसा किया

एच ऑन।

7

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास

1.6 .सेफेमा को "अवैध रूप से अधिग्रहित ए" को ज़ब्त करने का निर्देश दिया गया है

धारा 2 (2) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आने वाले व्यक्ति की संपत्तियां।रिश्तेदारों और सहयोगियों को केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया जाता है कि दोषी या बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, उनके नाम पर अर्जित या रखी गई संपत्ति, अधिनियम के जाल से न बचे।यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति अपनी संपत्ति के नाम पर इस तरह की अवैध गतिविधि से अर्जित बी संपत्तियों की जांच करते हैं।

तीव्स और सहयोगी।कभी-कभी वे स्वामित्व और स्वामित्व को हस्तांतरित करने के इरादे से ऐसी संपत्तियों को उन्हें हस्तांतरित करते हैं।वास्तव में, यह महत्वपूर्ण है कि कैसे ऐसे रिश्तेदार या सहयोगी के पास विक्ट/डिटेन्यू की संपत्तियां हैं, चाहे वे बेनामी के

रूप में हों या केवल नाम-ऋणदाता के रूप में या मूल्य के लिए या किसी अन्य तरीके से एक प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता के रूप में। वह उन संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकता है और उसे अधिनियम के तहत उन्हें राज्य को सौंप देना चाहिए।चूँकि वह रिश्तेदार या सहयोगी है, जैसा कि अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, वह यह साबित होने के बाद कोई बचाव नहीं कर सकता है कि उस संपत्ति को बंदी द्वारा अधिग्रहित किया गया था-चाहे वह उसके अपने नाम पर हो या उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर।यह धारा 2 (2) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित डी व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए या अपनाए जा सकने वाले कई उपकरणों का प्रतिकार करने के लिए है कि उक्त उप-धारा के खंड (सी) और (डी) में उल्लिखित उनके संबंध और सहयोगी भी अधिनियम के दायरे में लाए गए हैं।उनके तथ्य

दोषी/बंदी की संपत्तियों को रखने या रखने से दोषी/बंदी और उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच संबंध स्थापित होता है। केवल दोषी/बंदी की संपत्तियों को जब्त करने की मांग की जाती है, चाहे वे कहीं भी हों।विचार यह है कि उसकी संपत्तियों तक पहुँचा जाए जिनके नाम पर उन्हें रखा गया है या जिनके द्वारा भी उन्हें रखा गया है।रिश्तेदारों और दोस्तों की स्वतंत्र संपत्तियां, जो दोषी/बंदी के लिए पता लगाने योग्य नहीं हैं, को जब्त करने की मांग नहीं की जाती है और न ही वे SAFEMA के दायरे में हैं। [44 - बी-जी] एफ उन संपत्तियों और दोषी/बंदी के बीच जुड़ाव होना चाहिए, जिसे गलत साबित करने का बोझ रिश्तेदार/सहयोगी पर है।इस प्रकार धारा 2 (2) के खंड (ई) में उल्लिखित रिश्तेदारों और सहयोगियों या व्यक्तियों को लाना अनुच्छेद 31-बी के संरक्षण के अलावा न तो आपराधिक है और न ही अक्षम है।जी [46-जी-एच और 47-ए] 1.7।कोफेपोसा की धारा 5-ए अमान्य या अमान्य नहीं है।यह अनुच्छेद 22 के खंड (5) का उल्लंघन नहीं है।[54 - ई]

1.8 .नजरबंदी का आदेश एक ही आधार पर हो सकता है।यह एच 8

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. ए. आवश्यक नहीं है कि निरोध के आदेश को बनाने या बनाए रखने के लिए कई आधार होने चाहिए।जहाँ निरोध का आदेश एक से अधिक आधारों पर दिया जाता है, वह धारा एक कानूनी कल्पना का निर्माण करती है, अर्थात।, यह माना जाना चाहिए कि हिरासत के उतने ही आदेश हैं जितने आधार हैं जिसका अर्थ है कि ऐसे प्रत्येक आदेश एक स्वतंत्र आदेश है।यह है।

अनुच्छेद 22 (5) और के बीच किसी भी विसंगति या संघर्ष की कल्पना करना मुश्किल है।

धारा 5-ए।संसद एक कानूनी कल्पना बनाने के लिए सक्षम है और उसने इस मामले में ऐसा किया।अनुच्छेद 22 (5) अलग-अलग आधारों पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक साथ एक से अधिक आदेश देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।[48 - जी, 49-डी-ई]

देबू महतो बनाम।पश्चिम बंगाल राज्य, [1974] 4 एस. सी. सी. 135; अनिल डे बनाम।

एस.

पश्चिम बंगाल राज्य, [1974] 4 एस. सी. सी. 514; इजरायल एस. के. बनाम।पश्चिम दिनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य।, [1975] 3 एस. सी. सी. 292; धारुआ कानू बनाम।पश्चिम बंगाल राज्य, [1975] 3 एस. सी. सी. 527; सरस्वती शेषगिरी बनाम।केरल राज्य और अन्य।, [1982] 2 एस. सी. सी. ने भरोसा किया।

डी.

के. यादगिरी रेड्डी बनाम।पुलिस आयुक्त, आईएलआर (1972) एपी 1025,

प्रतिष्ठित।सिविल अपील न्यायनिर्णयः1978 की स्थानांतरण याचिका सं. 17 आदि। आदि।

4

ई.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 139 ए के तहत)

अल्ताफ अहमद, एडिशनल।सॉलिसिटर जनरल, वेणुगोपाल रेड्डी, डॉ. एन. एम. घटाटे, ए. के. श्रीवास्तव, सुश्री ए. सुभाषिनी, सुश्री सुषमा सूरी, पी. एच. पारेख, सुश्री प्रेरणा कोहली, ए. एस. भासमे, डी. पी. मुखर्जी, आर. एस. सूरी, के. सी. एफ. दुआ,

एस. के. अग्निहोत्री, हरजिंदर सिंह, आर. ए. श्रॉफ, मेसर्स मित्तर एंड कंपनी के लिए सर्व मित्तर, एस. गणेश, के. जे. जॉन, जी. एस. फाले, प्रमोद स्वरूप, सुश्री जे. सरला, एम. एन. श्रॉफ, नंद कुमार, ई. सी. अग्रवाल,

तंबवेकर, पी. परमेस्वरन, पी. के. पिल्लई, ए. टी. एम. संपत, एम. वीरप्पा, के. आर. नाम्बियार, अम्बरीश कुमार, टी. एस. अरोड़ा, सी. वी. एस. राव, एस. फजल, यू. सागर, जी. सुश्री सारदा देवी, यशांक, मुकुल मुद्गल, डी. गोबर्धन, एस. एम. जाधव, साकेश कुमार, आर. एन. जोशी, सुश्री जानकी रामचंद्रन, यू. ए. राणा, आनंद प्रसाद, एम/एस गागरेट एंड कंपनी के लिए राजीव त्यागी, पी. आर. सीतारमन, एम. टी. जॉर्ज, एस. के. गंभीर और आर. एस. सोधी उपस्थित दलों के लिए।एच न्यायालय का निर्णय अटॉर्नी जनरल द्वारा दिया गया था।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.] 9 बी. पी. जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे. उदारीकरण की हवा शुरू होने तक ए

पिछले एक-दो वर्षों में भारतीय आर्थिक परिदृश्य में उथल-पुथल मचाने वाली भारतीय अर्थव्यवस्था एक सुरक्षित स्थिति में थी। स्वतंत्रता के समय, भारत के पास नाम के लायक औद्योगिक आधार नहीं था।एक मजबूत औद्योगिक आधार स्थापित करना पड़ा। भारी उद्योग की अत्यधिक आवश्यकता थी।इन सब के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता थी।द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निर्मित उत्कृष्ट संतुलन तेजी से समाप्त हो रहे थे।विदेशी मुद्रा को संरक्षित करना पड़ा, जिसका अर्थ था कई अनावश्यक वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध और अन्य आयातों का करीबी विनियमन।नवजात उद्योगों को पोषित करने और प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षात्मक दीवारें खड़ी करना भी आवश्यक पाया गया।इन नियंत्रणों का कितना भी दुर्भाग्यपूर्ण पतन हुआ।उन्होंने तस्करों और विदेशी मुद्रा में हेरफेर करने वालों के एक वर्ग को जन्म दिया जो नियमों सी और प्रतिबंधों को विफल करने के लिए तैयार थे-लाभ उनका एकमात्र उद्देश्य था, और जीवन में सफलता सही और गलत का एकमात्र सांसारिक न्यायाधीश था।1947 की शुरुआत में, केंद्रीय विधानमंडल ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 और आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को लागू करना आवश्यक पाया।इसके बाद आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 आया जिसमें आयात के संबंध में नीति को निश्चित आधार पर रखा गया।डी वर्ष 1962 में, एक नए सीमा शुल्क अधिनियम ने प्राचीन समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 को बदल दिया।हालाँकि, तस्करी और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन का खतरा बेरोकटोक बढ़ता रहा।इसके बाद संसद विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1974 (कोफेपोसा) के साथ आगे आई।इसने इन असामाजिक लोगों को निवारक हिरासत में रखने का प्रावधान किया

तत्व।25 जून, 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा की।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के तहत इस आधार पर कि "आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को खतरा है"।3 दिसंबर, 1971 को अनुच्छेद 352 (1) के तहत इस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई कि "भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण से खतरा है" पहले से ही लागू था।इन घोषणाओं का प्रभाव 'निलंबन' का था-एक लोकप्रिय लेकिन कड़ाई से सटीक अभिव्यक्ति का उपयोग करने के लिए-संविधान के अनुच्छेद 358 द्वारा प्रदान किया गया अनुच्छेद 19।27 जून, 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 359 (1) के तहत एक आदेश दिया जिसमें जी.

" कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी व्यक्ति (एक विदेशी सहित) का किसी भी अदालत में जाने का अधिकार और

संविधान का अनुच्छेद 22 और उपर्युक्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय में लंबित सभी कार्यवाही उस अवधि के लिए निलंबित रहेगी जिसके दौरान 3 दिसंबर, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (1) के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी।

10

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. ए. 25 जून, 1975 दोनों लागू हैं।

1 जुलाई, 1975 से कोफेपोसा में कुछ मामलों में संशोधन किया गया था।अन्य बातों के साथ-साथ, इसने धारा 12-ए पेश की जिसमें आपातकाल से निपटने के लिए विशेष प्रावधान हैं।धारा 12-ए के आधार पर, आधारों की आपूर्ति की आवश्यकताएँ [धारा 3 (3)] और सलाहकार बोर्ड के साथ परामर्श

(धारा 8) को व्यावहारिक रूप से समाप्त कर दिया गया।वर्ष 1976 में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपातकाल के जारी रहने के दौरान, संसद ने तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों को अधिनियमित किया।

(संपत्ति की जब्ती) अधिनियम, 1976 (सेफेमा)।यदि किसी अध्यादेश को उसी प्रभाव से प्रतिस्थापित किया जाता है और अध्यादेश की तारीख से लागू किया गया था, अर्थात।, 5 नवंबर, 1975।यह अधिनियम समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878/सीमा शुल्क अधिनियम, 1962/एफ. ई. आर. ए., 1947/एफ. ई. आर. ए., 1973 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों और कोफेपोसा के तहत हिरासत में लिए गए लोगों पर लागू होता है, जिनके निरोध आदेश

उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में न तो अलग किया गया और न ही निरस्त किया गया।घ. इस प्रकार दोषी ठहराए गए/हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के अलावा, यह अधिनियम उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों पर भी लागू होता है।इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ऐसे तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना है, जिनके नाम पर उन्हें रखा गया हो।

25 जून, 1975 को घोषित आपातकाल की अवधि के दौरान, अधिनियम की धारा 3 के तहत हिरासत के कई आदेश दिए गए थे।

ई.

कोफेपोसा।धारा 12-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, उक्त बंदियों को न तो हिरासत के आधार प्रदान किए गए थे और न ही उनके मामलों को सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था।हालाँकि, बंदियों के पास कोई उपाय नहीं था।अनुच्छेद 359 (1) के तहत आदेश और अनुच्छेद 358 के संचालन के कारण, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा ए. डी. एम. जबलपुर बनाम में व्याख्या की गई है।शिवकांत शुक्ला, [1976] 2 एस. सी. सी. 521-वे राहत के लिए उच्च न्यायालय या इस न्यायालय से संपर्क नहीं कर सके। 21 मार्च, 1977 को आपातकाल को समाप्त कर दिया गया और बंदियों को रिहा कर दिया गया।इसके बाद धारा 6 के तहत नोटिस जारी किए गए।

च

एल.

SAFEMA ने कथित बंदियों, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों से आह्वान किया कि वे कारण दिखाएं कि नोटिस में उल्लिखित संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के रूप में घोषित क्यों नहीं किया जाए और जब्त क्यों नहीं किया जाए।आपातकाल की अवधि के दौरान कोफेपोसा के तहत हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ हिरासत के आदेशों के कारण उनके खिलाफ सेफेमा लागू किया जा रहा था।ने कहा कि

नजरबंदी के आदेश जोड़ने वाली कड़ी थे, हिरासत में लिए गए लोगों, उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की नींव

एच. सेफेमा।(नजरबंदी के आदेश, यह विवाद में नहीं है, रद्द नहीं किए गए थे

जी एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी, जे.) 11 या सेफेमा की धारा 2 ए की उप-धारा (2) के खंड (बी) द्वारा विचार के अनुसार अलग रखा गया है)।यह तब है जब उक्त व्यक्तियों ने उक्त नोटिसों को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों और अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।इन रिट याचिकाओं में, कोफेपोसा, सेफेमा और भारत के संविधान के 39 वें, 40 वें और 42 वें संशोधनों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए थे।(कुछ मामलों में, ऐसा प्रतीत होता है, अंतिम बी

आदेश भी पारित किए गए थे-लेकिन उस परिस्थिति से इसमें शामिल सिद्धांत में कोई अंतर नहीं पड़ता है)।अधिकांश मामलों में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी गई।

भारत के महान्यायवादी ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाओं को इस न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन किया ताकि सी की सुनवाई इस न्यायालय में सीधे की जाने वाली याचिकाओं के साथ की जा सके।इसमें महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए गए।स्थानांतरण के लिए प्रार्थना सभी स्थानांतरण याचिकाओं में दी जाती है।एस. एल. पी. में दी गई छुट्टी का उल्लेख किया जा सकता है कि कोफेपोसा को नौवें में रखा गया था।

एस 1 पर अनुसूची बनाएँ।संविधान 39 वें (संशोधन) अधिनियम, 1975 डी द्वारा संख्या 104 जबकि सेफेमा और कोफेपोसा (संशोधन) अधिनियम, 1976

(केंद्रीय अधिनियम क्रमशः 1976 के 13 और 20) को 9 वें में रखा गया था।

अनुसूचिका क्र. सं.127 और संविधान 40 वें (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा 129।

ई.

याचिकाकर्ताओं के वकील ने कई दलीलों का आग्रह किया, जिनमें से सभी को तीसरे अल्ताफ अहमद, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा चुनौती दी गई है।बार में आग्रह किए गए प्रतिद्वंद्वी विवादों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों को प्रश्नों के रूप में तैयार किया जा सकता है।इनका प्रभाव निम्नलिखित हैः

च

(1) क्या संसद कोफेपोसा और सेफेमा को लागू करने के लिए सक्षम नहीं थी?

(2) क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 (1) के तहत घोषित आपातकाल की अवधि के दौरान कोफेपोसा की धारा 12-ए के साथ पठित धारा 3 के तहत हिरासत का आदेश-अनुच्छेद 19 के परिणामी 'निलंबन' के साथ और किस अवधि के दौरान अनुच्छेद 14,21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने का अधिकार निलंबित कर दिया गया था-बंदी, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के खिलाफ सेफेमा की धारा 6 के तहत कार्रवाई करने की नींव बना सकता है?और अगर ऐसा होता है, तो क्या हिरासत के इस तरह के आदेश की वैधता को हिरासत में लिए गए एच सुपर कोर्ट रिपोर्ट [1994] एसयूपीपी द्वारा चुनौती दी जा सकती है।

1 एस सी आर।

12

ए और/या घंटे रिश्तेदार और सहयोगी, जब उनके खिलाफ SAFEMA के तहत कार्यवाही की जाती है, भले ही हिरासत के उक्त आदेश को लागू करना बंद कर दिया गया हो और या तो चुनौती नहीं दी गई थी-या इसके संचालन के दौरान सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी गई थी?

(3) यदि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या निरोध के आदेश की बी वैधता का परीक्षण उक्त आदेश देने के समय और उसके संचालन की अवधि के दौरान प्राप्त कानून की स्थिति के संदर्भ में या सेफमा की धारा 6 के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करने की तारीख को प्राप्त कानून की स्थिति के संदर्भ में किया जाना चाहिए?

(4) क्या खंड में "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" की परिभाषा

ग

(सेफेमा की धारा 3 (1) का ग) अनुच्छेद 14,19 और 21 द्वारा गारंटीकृत याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और क्या संविधान की नौवीं अनुसूची में सेफेमा का समावेश इस तरह के उल्लंघन, यदि कोई हो, को ठीक करता है?

(5) क्या रिश्तेदारों के लिए सेफेमा का आवेदन और के रूप में

डी.

बंदियों का समाज अनुच्छेद 14,19 और 21 का उल्लंघन करता है?क्या 9 वीं अनुसूची में उक्त अधिनियम को शामिल करने से इस तरह के उल्लंघन को ठीक किया जा सकता है, यदि कोई हो?(6) क्या कोफेपोसा की धारा 5-ए अनुच्छेद 22 के खंड (5) का उल्लंघन है?

ई.

उपरोक्त प्रश्नों की उचित समझ के लिए, दोनों अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को संक्षेप में संदर्भित करना आवश्यक है।

{ कोफेपोसा-अधिनियम की प्रस्तावना उन कारणों और उद्देश्यों की व्याख्या करती है जिनके लिए अधिनियम बनाया गया था। इसमें लिखा हैः

च

}

" विदेशी मुद्रा विनिमय के संरक्षण और तर्क के उद्देश्यों और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम और उससे जुड़े मामलों के लिए कुछ मामलों में निवारक निरोध का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम।

जी.

¿ जबकि विदेशी मुद्रा नियमों और स्मग का उल्लंघन

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर तेजी से हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है और इस तरह राज्य की सुरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

एच.

और उन व्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए जिनके द्वारा और अटॉर्नी जनरल।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी, जे.) 13 तरीका जिसमें ऐसी गतिविधियाँ या उल्लंघन आयोजित किए जाते हैं और ए को आगे बढ़ाया जाता है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुछ क्षेत्रों में जो तस्करी के लिए अत्यधिक संवेदनशील हैं, एक महत्वपूर्ण परिमाण की तस्करी गतिविधियों को गुप्त रूप से आयोजित किया जाता है और चलाया जाता है, ऐसी गतिविधियों और उल्लंघनों की प्रभावी रोकथाम के लिए किसी भी बी तरीके से संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में रखने का प्रावधान करना आवश्यक है।

चाहे वह भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाएः11

"तस्करी" शब्द को धारा 2 के खंड (ई) में परिभाषित किया गया है।इसमें कहा गया है कि उक्त अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (39) में है और इसके सभी व्याकरणिक परिवर्तनों और संज्ञानात्मक अभिव्यक्तियों का अर्थ उसी के अनुसार लगाया जाएगा।

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 का खंड (39) "तस्करी" को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित करता हैः "किसी भी माल के संबंध में तस्करी का अर्थ है कोई ऐसा कार्य या चूक जो ऐसे माल को धारा 111 या धारा 113 के तहत जब्त करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

धारा 3 में प्रावधान है कि जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उस ओर से सशक्त कोई अधिकारी ई से संतुष्ट है

किसी विदेशी सहित किसी व्यक्ति के संबंध में, कि (1) उसे संरक्षण के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से या

विदेशी मुद्रा में वृद्धि या (2) उसे (i) माल की तस्करी, या (ii) माल की तस्करी को बढ़ावा देना, या (iii) माल के परिवहन या छिपाने या तस्करी में शामिल होना, या (iv) तस्करी किए गए माल का लेन-देन करना, या तस्करी किए गए माल को परिवहन या छिपाने या तस्करी में शामिल होने के अलावा, या (v) माल की तस्करी में लगे व्यक्तियों को शरण देना या माल की तस्करी को बढ़ावा देना, उसे हिरासत में लेना आवश्यक है, वह ऐसा कर सकता है।उप-धारा (3) निरोध के पांच दिनों के भीतर निरोध के आधार की सेवा प्रदान करती है।("असाधारण परिस्थितियों और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों" में, हिरासत जी के आधार को पंद्रह दिनों के भीतर पूरा करने की अनुमति है)।

धारा 5-ए, जिसे 1975 के संशोधन अधिनियम 35 द्वारा जोड़ा गया था, इस प्रकार हैः

" 5 - ए.हिरासत के आधार जहां कोई व्यक्ति एच "रहा है, अलग किए जा सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस सी आर।

क.

उप-धारा के तहत निरोध के आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया गया

(1) धारा 3 की, जो दो या अधिक आधारों पर की गई है, निरोध का ऐसा आदेश किया गया समझा जाएगा।

ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग-अलग और तदनुसार

| ((क) ऐसा आदेश अमान्य या अमान्य नहीं माना जाएगा।

केवल इसलिए कि एक या कुछ आधार हैं या हैं-(i) अस्पष्ट,

((ii) गैर-मौजूद,

एस.

((ग) प्रासंगिक नहीं है,

((iv) ऐसे व्यक्ति से न तो जुड़ा हुआ है और न ही निकटता से जुड़ा हुआ है, या

(v) किसी भी अन्य कारण से अमान्य,

डी.

और इसलिए यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि ऐसा आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी को धारा 3 की उप-धारा (1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संतुष्ट किया गया होगा।

आधार या आधार और निरोध का आदेश दिया;

ई.

(ख) नजरबंदी का आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी

यह समझा जाए कि उसने उक्त उप-धारा (1) के तहत उस उप-धारा में दिए गए प्रावधानों के अनुसार संतुष्ट होने के बाद निरोध का आदेश दिया है।

शेष मैदान या मैदान के संदर्भ में।

1

इस खंड के बारे में अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी।

च

धारा 8 आवश्यकतानुसार एक सलाहकार मंडल के गठन का प्रावधान करती है।

अनुच्छेद 22 के खंड (4) द्वारा और प्रत्येक बंदी के मामले को इसके लिए संदर्भित करने के लिए।सलाहकार मंडल की राय सरकार के लिए बाध्यकारी है।

धारा 9 मामलों के कुछ वर्गों का प्रावधान करती है, जहां सलाहकार जी बोर्ड का संदर्भ एक विस्तारित अवधि के भीतर किया जा सकता है।यह धारा अनुच्छेद 22 के खंड (7) से संबंधित है।आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधानों वाली धारा 12-ए कोफेपोसा (संशोधन) द्वारा पेश की गई थी।

अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम 19)।इसकी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता को देखते हुए, खंड को पूरी तरह से निर्धारित किया जा सकता है।इसमें लिखा हैः

एच.

" 12 - ए.आपात स्थिति से निपटने के लिए विशेष प्रावधान।- (1) नहीं।

15

1 एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.]

इस अधिनियम या प्राकृतिक न्याय के किसी भी नियम में निहित कुछ भी होने के बावजूद, इस धारा के प्रावधान जारी किए गए आपातकाल की घोषणा के संचालन की अवधि के दौरान प्रभावी होंगे।

संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड (i) के तहत 3 दिसंबर, 1971 को या उस खंड के तहत जून, 1975 के 25 वें दिन जारी आपातकाल की घोषणा या बी की अवधि के तहत

25 जून, 1975 से चौबीस महीने, जो भी अवधि सबसे छोटी हो।

(2) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम (संशोधन) सी अधिनियम, 1975 के प्रारंभ के बाद किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस अधिनियम के तहत हिरासत का आदेश देते समय, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, हिरासत का आदेश देने वाला अधिकारी इस बात पर विचार करेगा कि क्या इस अधिनियम के तहत ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना आवश्यक है या नहीं।

जिन उप-धारा (1) में निर्दिष्ट घोषणाओं को जारी किया गया है (इसके बाद इस धारा में आपातकाल के रूप में संदर्भित) और यदि, इस तरह के विचार पर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आपातकाल से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ऐसे व्यक्ति को हिरासत में रखना आवश्यक है, तो सरकार या अधिकारी उस आशय की घोषणा कर सकते हैं और घोषणा की एक प्रति संबंधित व्यक्ति को भेज सकते हैंः

बशर्ते कि जहां ऐसी घोषणा किसी अधिकारी द्वारा की जाती है, वहां घोषणा करने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपयुक्त सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जाएगी और ऐसी घोषणा एफ का प्रभाव तब तक समाप्त हो जाएगा जब तक कि उस सरकार द्वारा ऐसी समीक्षा के बाद पंद्रह दिनों की उक्त अवधि के भीतर इसकी पुष्टि नहीं की जाती है।(3) यह प्रश्न कि क्या किसी ऐसे व्यक्ति को हिरासत में लेना, जिसके संबंध में उप-धारा (2) के तहत घोषणा की गई है, आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है, उपयुक्त सरकार द्वारा ऐसी घोषणा की तारीख से चार महीने के भीतर और उसके बाद चार महीने से अधिक नहीं के भीतर पुनर्विचार किया जाएगा, और यदि, इस तरह के पुनर्विचार पर, उपयुक्त सरकार को यह प्रतीत होता है कि एच के साथ प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यक्ति को हिरासत में लेना अब आवश्यक नहीं है।

जी 16

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. आपातकाल, कि सरकार घोषणा को रद्द कर सकती है।

क.

(4) उप-धारा (2) या (3) के तहत कोई विचार, समीक्षा या पुनर्विचार करने में, उपयुक्त सरकार या अधिकारी, यदि ऐसी सरकार या अधिकारी इसे जनता के खिलाफ समझता है, तो कर सकता है।

अन्यथा करने का हित, सूचना के आधार पर कार्य करना और

तथ्यों का खुलासा किए बिना या संबंधित व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए बिना अपने कब्जे में सामग्री।

(5) किसी निरोध आदेश के तहत हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को खुलासा करना आवश्यक नहीं होगा, जिस पर उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं।

एस.

जिन आधारों पर आदेश उस अवधि के दौरान दिया गया है, उस उप-धारा के तहत ऐसे व्यक्ति के संबंध में की गई घोषणा लागू है और तदनुसार, ऐसी अवधि को धारा 3 की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

डी.

(6) निरोध आदेश के तहत हिरासत में लिए गए प्रत्येक व्यक्ति के मामले में

जिस पर उप-धारा (2) के प्रावधान लागू होते हैं, वह व्यक्ति होने के नाते जिसके संबंध में उसके तहत घोषणा की गई है,

जिस अवधि के दौरान ऐसी घोषणा लागू है, उसे गणना के उद्देश्य से ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

ई.

(i) धारा 8 के खंड (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अवधि;

!

((ii) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट "एक वर्ष" और "पाँच सप्ताह" की अवधि, उप-धारा (2) (i) में विनिर्दिष्ट "एक वर्ष" की अवधि और उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट "छह महीने" की अवधि।

धारा 9 की धारा (3) "।

च

यह प्रावधान आपातकाल की अवधि के दौरान किया गया था और

आपातकाल की अवधि या ऐसी छोटी अवधि तक सीमित जो निर्दिष्ट की जा सकती है।यह एक घोषणा करने पर विचार करता है कि आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए व्यक्ति की नजरबंदी आवश्यक है और यदि ऐसी जी घोषणा की जाती है, तो उसका मामला इस धारा द्वारा शासित होगा।एकमात्र सुरक्षा उपाय पी यदि उन्हें ऐसा कहा जा सकता है-धारा में उल्लिखित उपयुक्त सरकार द्वारा समीक्षा और पुनर्विचार के प्रावधान हैं।

स्वयं।अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) में संवैधानिक सुरक्षा उपायों और उक्त सुरक्षा उपायों को शामिल करने वाले अधिनियम के प्रावधानों को हटा दिया गया है।

एच के साथ इस अर्थ में कि उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है; कई बार अटॉर्नी जनरल।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी, जे.) धारा 8 और 9 में निर्धारित 17 सीमाएँ ए. की अवधि तक बढ़ा दी गई हैं।

आपात स्थिति।

सेफेमाःअधिनियम की प्रस्तावना कारणों को निर्धारित करती है और

अधिनियम के पीछे की वस्तुएँ।इसमें लिखा हैः

" अवैध रूप से अर्जित उचित सामान को जब्त करने के लिए एक अधिनियम-तस्करों और विदेशी मुद्रा में हेरफेर करने वालों के बी संबंध और चटाई के लिए

इसके साथ जुड़े या प्रासंगिक;

दे।

जबकि तस्करी गतिविधियों और विदेशी मुद्रा हेरफेर की प्रभावी रोकथाम के लिए जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव डाल रहे हैं, ऐसी गतिविधियों और हेरफेर में लगे व्यक्तियों को उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करना आवश्यक है।

और जबकि ऐसे व्यक्ति इस तरह के लाभ को बढ़ा रहे हैं

धन-कर, आय-कर या अन्य कानूनों या अन्य डी साधनों के उल्लंघन द्वारा और इस तरह संचालन के लिए अपने संसाधनों में वृद्धि कर रहे हैं।

एक गुप्त तरीके से;

और जबकि ऐसे व्यक्तियों ने कई मामलों में ई के नाम से इस तरह के लाभ के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को धारण किया है।

उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों और विश्वासपात्रों से;

चाहे वह संसद द्वारा 26 वें वर्ष में अधिनियमित किया गया हो।

भारत गणराज्य इस प्रकार हैः "

धारा 2 उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जिन पर अधिनियम लागू होता है।उप-धारा (1) घोषणा करती है कि अधिनियम के प्रावधान "केवल उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर" लागू होंगे।उप-धारा (2) उन व्यक्तियों की पाँच श्रेणियों का उल्लेख करती है जिन पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं।प्रथम श्रेणी के पुरुष

खंड (ए) के तहत उल्लिखित व्यक्तियों में समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत एक लाख रुपये से अधिक मूल्य के सामान के संबंध में अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति शामिल हैं।जी रुपये एक लाख से अधिक मूल्य की आवश्यकता दूसरी या बाद की स्थिति के मामले में लागू नहीं होती है।एफ. ई. आर. ए., 1947/1973 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति, जिसमें शामिल राशि और मूल्य एक लाख रुपये से अधिक है, भी शामिल हैं।

खंड (ए) के तहत।हालांकि, मूल्य की आवश्यकता (एक लाख से अधिक) दूसरी या बाद की सजा के मामले में लागू नहीं होती है। दूसरी श्रेणी [खंड (बी)] में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनके संबंध में एच का आदेश

एफ 18

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. को कोफेपोसा के तहत हिरासत में लिया गया है, लेकिन किस आदेश को परंतुक के चार उपखंडों में निर्धारित किसी भी स्थिति में रद्द या अलग नहीं किया गया था।खंड (ख) को पूरी तरह से निर्धारित करना उचित होगा।इसमें लिखा हैः "(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण के तहत निरोध का आदेश दिया गया है और

तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (1974 का 52):बशर्ते कि -

((i) निरोध का ऐसा आदेश, एक ऐसा आदेश है जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12-ए के प्रावधान नहीं हैं।

एस.

उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले या विज्ञापन का संदर्भ देने से पहले रद्द नहीं किया गया है।

मुखपट बोर्ड; या

((ख) निरोध का ऐसा आदेश, जिसके लिए -

डी.

उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान लागू होते हैं, धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत समीक्षा के लिए या उसके आधार के लिए समय की समाप्ति से पहले या उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर निरस्त नहीं किए गए हैं।

अधिनियम, या

ई.

((ग) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12-क के प्रावधान लागू होते हैं, उस धारा की उप-धारा (3) के तहत पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर या धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर समय समाप्त होने से पहले रद्द नहीं किया गया है।

च

उस अधिनियम की धारा 12-ए की उप-धारा (6), या

((iv) निरोध के ऐसे आदेश को अदालत द्वारा दरकिनार नहीं किया गया है।

सक्षम अधिकारिता; 17

तीसरी श्रेणी जिसके लिए अधिनियम लागू होता है (खंड (सी) में उल्लिखित)

जी.

खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के रिश्तेदार हैं।चौथी श्रेणी [खंड (घ)] में खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के सहयोगी शामिल हैं।खंड (ई) के तहत उल्लिखित पांचवीं श्रेणी किसी भी संपत्ति के धारकों से संबंधित है, जो पहले किसी भी समय खंड (ए) या (बी) में निर्दिष्ट व्यक्ति के पास थी, जब तक कि ऐसा धारक यह साबित न कर दे कि एच वह अच्छी भावना से मूल्यवान प्रतिफल के लिए हस्तांतरणकर्ता है।व्याख्या (1)

19

एटॉर्नी जनरल, भारत के लिए बनाम।ए. प्रजीवंदास जीवन रेड्डी।जे.]

खंड (ए) में उल्लिखित मूल्य की गणना किस तरीके से की जानी है, यह निर्दिष्ट करता है।स्पष्टीकरण (2) खंड (ग) द्वारा कवर किए गए रिश्तेदारों को निर्दिष्ट करता है, जबकि स्पष्टीकरण (3) खंड (घ) के तहत शामिल सहयोगियों को निर्दिष्ट करता है।धारा 3 अधिनियम में आने वाली कुछ अभिव्यक्तियों को परिभाषित करती है, जिसमें "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" अभिव्यक्ति भी शामिल है।वह इस प्रकार हैः

" (ग) "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति", किसी भी व्यक्ति के संबंध में जिसके लिए यह अधिनियम लागू होता है, इसका अर्थ है

} .

((i) ऐसे व्यक्तियों द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी आय, आय या परिसंपत्तियों के माध्यम से या किसी ऐसी गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त की गई या उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसके संबंध में संसद को अधिकार है।

कानून; या

डी.

((ख) ऐसी व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी आय, आय या संपत्ति के माध्यम से या जिसके संबंध में ऐसी किसी कानून का उल्लंघन किया गया है; या

((ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, किसी भी आय, आय या संपत्ति से या उसके माध्यम से पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जिसका स्रोत साबित नहीं किया जा सकता है और जिसे किसी

ऐसे मामले के संबंध में किए गए किसी कार्य या चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है।

या

((iv) इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में, ऐसे व्यक्ति द्वारा अधिग्रहित कोई भी संपत्ति, किसी भी संपत्ति के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से पता लगाने योग्य, किसी विचार के लिए, या किसी भी माध्यम से

उपखंड (i) से (iii) या ऐसी संपत्ति से आय या आय जी में संदर्भित;

और इसमें शामिल हैं

(ए) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारण की गई कोई भी संपत्ति जो उसके किसी पूर्व धारक के संबंध में होती, जिसने अवैध रूप से एच 20 अर्जित किया होता।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 इस खंड के तहत एस. सी. आर. संपत्ति यदि ऐसे पूर्व धारक के पास नहीं थी

क.

इसे धारण करना बंद कर दिया, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो ऐसे पूर्व धारक के बाद किसी भी समय संपत्ति रखता था या जहां दो या दो से अधिक ऐसे पूर्व धारक हैं, अंतिम

1

ऐसे पिछले धारकों में से पर्याप्त विचार के लिए सद्भावना से अंतरिती है या था;

(बी) ऐसी व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, मद (ए) के तहत आने वाली किसी संपत्ति के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से पता लगाने योग्य, या उससे होने वाली आय या आय पर विचार करने के लिए;

एस.

↑

इस परिभाषा के बारे में अधिक जानकारी बाद में दी जाएगी।

धारा 4 घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ के बाद, यह किसी भी व्यक्ति के लिए विधिसम्मत नहीं होगा, जिसके लिए यह अधिनियम लागू होता है, किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसके पास रखना वैध नहीं होगा।

डी की ओर से।इस प्रकार धारण की गई कोई भी संपत्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के लिए जब्त की जा सकती है।धारा 6 में प्रावधान है -

जब कि धारा 7 में इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने का प्रावधान है, ज़ब्त करने का कारण दिखाएँ नोटिस जारी करना। धारा 8 में कहा गया है कि अधिनियम के तहत कार्यवाही में, यह साबित करने का बोझ कि धारा 6 के तहत दी गई सूचना में निर्दिष्ट कोई भी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, प्रभावित व्यक्ति पर होगा।धारा 11 धारा 6 के तहत जारी सूचना में निर्दिष्ट संपत्तियों के हस्तांतरण को अमान्य घोषित करती है, जो सूचना जारी होने के बाद प्रभावी होती है।धारा 12 में धारा 7 के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है।धारा 24 उस समय लागू किसी भी अन्य कानून पर अधिनियम को एक प्रबल प्रभाव देती है।

च

यहाँ उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर चर्चा करने से पहले, कुछ स्पष्टीकरणात्मक टिप्पणियां करना आवश्यक है।यद्यपि संविधान के 39 वें, 40 वें और 42 वें संशोधनों की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उक्त संशोधन-केशवानंद भारती बनाम में निर्णय के बाद प्रभावी हुए थे।राज्य

जी.

केरल का, [1973] पूरक।एस. सी. आर. 1 संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करता है, इसे साबित करने के लिए तर्कों के दौरान कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया था।आम तौर पर यह तर्क दिया जाता था कि अनुच्छेद 14 संविधान की बुनियादी विशेषताओं में से एक है और इसलिए अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल संरचना का समान रूप से उल्लंघन करता है।यह सरल 'एच' तर्क अनुच्छेद 31-बी के कारण को नजरअंदाज करता है-किसी भी तरह से, इसका अटॉर्नी जनरल।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.] 21 भारती और 39 वें और 40 वें संशोधन के बाद निरंतरता और प्रासंगिकता-उक्त अधिनियमों को 9 वीं अनुसूची में रखने का विचार।याचिकाकर्ताओं के तर्क को स्वीकार करने का मतलब यह होगा कि भारती संविधान के बाद नौवीं अनुसूची में अधिनियमों को रखने वाले सभी संशोधनों के मामले में अनुच्छेद 31-बी का संरक्षण अनुच्छेद 14 के खिलाफ उपलब्ध नहीं होगा।वास्तव में, यह सुझाव दिया गया था कि अनुच्छेद 21 और 19 भी संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।यदि ऐसा है, तो इसका अर्थ होगा अनुच्छेद 31-बी का और अधिक संरक्षण।चाहे जो भी हो, उक्त चुनौती को साबित करने के लिए किसी भी प्रयास के अभाव में, हम उक्त की संवैधानिक वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते हैं।

संशोधन।हम उन्हें वैसे ही लेते हैं जैसे वे हैं, यानी हम उन्हें अच्छा और वैध मानते हैं।हमें यह भी कहना चाहिए कि वकील द्वारा यह स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है कि उक्त संशोधन अधिनियम किस तरह से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।

एस.

कोफेपोसा निवारक निरोध से संबंधित एक कानून है।वहाँ है

अनुच्छेद 22 के खंड (4) से खंड (7) के प्रावधानों के अनुरूप होना।जहां तक सेफेमा का संबंध है, यह निश्चित रूप से निवारक निरोध से संबंधित कानून नहीं है, हालांकि इसे विभिन्न तरीकों से एक ही उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है।जहां एक निवारक निरोध के माध्यम से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, वहीं दूसरा उन्हें उनके गलत तरीके से अर्जित लाभ से वंचित करके दंडित करना चाहता है।इस प्रकार सेफेमा एक ऐसा उपाय है जिसे सुरक्षा के लिए बनाया गया है

देश की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ कानून तोड़ने को हतोत्साहित करने का एक उपाय-विशेष रूप से, आर्थिक उल्लंघन।ई की वैधता को निर्धारित करने में प्रासंगिक और ऐसे आर्थिक उपायों के प्रावधानों की व्याख्या करने के मामले में प्रासंगिक सिद्धांत काफी अच्छी तरह से तय किए गए हैं।यह माना जाता है कि इस तरह के अधिनियमों के मामले में विधायिका को जोड़ों में अधिक खेल की अनुमति दी जानी चाहिए।जैसा कि आर. के. गर्ग बनाम में जे. भगवती ने बताया है।भारत संघ, [1982] 970 पर 1 एस. सी. आर. 947:

च

" अदालत को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि "कानून व्यावहारिक समस्याओं के लिए निर्देशित किया जाता है, कि आर्थिक तंत्र अत्यधिक संवेदनशील और जटिल है, कि कई समस्याएं एकवचन और आकस्मिक हैं, कि कानून अमूर्त प्रस्ताव नहीं हैं और अमूर्त इकाइयों से संबंधित नहीं हैं और अमूर्त समरूपता द्वारा मापा नहीं जाना है" कि सटीक ज्ञान और उपचार का अच्छा अनुकूलन हमेशा संभव नहीं होता है और यह कि "निर्णय काफी हद तक एक भविष्यवाणी है जो मामूली और आकस्मिक पर आधारित है।

अव्याख्यायित अनुभव "।विशेष रूप से आर्थिक मामलों में प्रत्येक कानून अनिवार्य रूप से अनुभवजन्य है और यह परीक्षण और त्रुटि विधि पर आधारित है और इसलिए यह सभी संभावित स्थितियों के लिए प्रदान नहीं कर सकता है या एच का अनुमान नहीं लगा सकता है।

जी 22 आई सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (1994)।1 एस सी आर।

क.

सभी संभावित दुरुपयोग।जटिल प्रयोगात्मक आर्थिक विधान में कठोरता और असमानताएँ हो सकती हैं, लेकिन केवल इसी कारण से इसे अमान्य नहीं माना जा सकता है।न्यायालय, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि सचिव बनाम में इंगित किया है, नहीं कर सकता है।सेंट्रल रीग रिफाइनिंग कंपनी (94 वकील एडन। 381), ऐसी क्रूरताओं और असमानताओं से राहत के लिए न्यायाधिकरणों में परिवर्तित किया जाए।

दुरुपयोग की संभावनाएं भी हो सकती हैं, लेकिन वह भी अपने आप में कानून को अमान्य करने का आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी कानून के लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि किसी दैवीय विवेक, विकृतियों और इसके कानून के दुरुपयोग से जो इसके प्रावधानों के अधीन लोगों द्वारा किया जा सकता है और इस तरह के विकृतियों और दुरुपयोग के खिलाफ प्रावधान किया जा सकता है।वास्तव में, इसके निर्माण पर कितना भी ध्यान दिया जाए, ऐसे कानून की कल्पना करना मुश्किल है जो विकृत मानव सरलता द्वारा दुरुपयोग किए जाने में सक्षम न हो।इसलिए न्यायालय को ऐसे विधान की संवैधानिकता का निर्णय अपने प्रावधानों की व्यापकता के आधार पर करना चाहिए, न कि इसकी खामियों या असमानताओं या इसके किसी भी प्रावधान के दुरुपयोग की संभावनाओं के आधार पर।अगर कोई कड़वाहट है,

एस.

डी.

असमानताएँ या दुरुपयोग की संभावनाएँ सामने आती हैं, विधायिका हमेशा कदम उठा सकती है और उपयुक्त संशोधनकारी कानून बना सकती है।यही व्यावहारिक दृष्टिकोण का सार है जिसे जटिल आर्थिक मुद्दों से निपटने में विधायिका का मार्गदर्शन और प्रेरणा करनी चाहिए।

(जोर दिया गया)

ई.

इसी प्रभाव के लिए फेडरेशन में टिप्पणियाँ (पृष्ठ 663 पर) हैं

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन बनाम।भारत संघ, [1989] 3 एस. सी. सी. 634, संविधान पीठ का निर्णय।

च

अधिकारियों को गुणा करना आवश्यक नहीं है।

प्रश्न संख्या 1:याचिकाकर्ताओं के लिए यह तर्क दिया जाता है कि कोफेपोसा से संबंधित नहीं है

संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-I की प्रविष्टि-9 इस प्रकार है -

जी.

इसके लिए प्रदान की गई निवारक हिरासत भारत की रक्षा, विदेश मामलों या सुरक्षा से जुड़े कारणों से नहीं है।यहां तक कि सूची-III की प्रविष्टि-3 भी, जो प्रस्तुत की जाती है, उक्त अधिनियमन की गारंटी नहीं देती है।जहाँ तक सेफेमा का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि यह सूची-I में किसी भी प्रविष्टि (1) से (96) या सूची-III में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित नहीं है।हम एच से सहमत होने के लिए तैयार नहीं हैं।कॉफेपोसा स्पष्ट रूप से अटॉर्नी जनरल के रूप में सूची-III की प्रविष्टि 3 से संबंधित है।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी, जे.) 23 यह राज्य की सुरक्षा ए से जुड़े कारणों के साथ-साथ समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए निवारक निरोध का प्रावधान करता है।जहाँ सूची-III की प्रविष्टि 3 "राज्य की सुरक्षा" की बात करती है, वहीं सूची-I की प्रविष्टि 9 "भारत की सुरक्षा" की बात करती है।जाहिर है, वे दो अलग और अलग अभिव्यक्तियाँ हैं।"किसी राज्य की सुरक्षा" एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है।कमजोर और कमजोर अर्थव्यवस्था वाला राज्य अपनी सुरक्षा की अच्छी तरह से रक्षा नहीं कर सकता है।यह आर्थिक उपनिवेशवादियों के लिए एक आसान शिकार होगा।हम ऐसे देशों के बारे में जानते हैं जहाँ आर्थिक नीतियाँ उस राज्य के हित से नहीं बल्कि बहु-राष्ट्रीय और/या अन्य शक्तिशाली देशों के हित

से निर्धारित होती हैं।एक कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश अक्सर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने के लिए बाध्य होता है जो बदले में उधार लेने वाले राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करना चाहते हैं-यह मायने नहीं रखता कि वे शक्तिशाली देशों के हित में ऐसा करते हैं जो अपने कोष में पर्याप्त योगदान देते हैं या अपने ऋण के ब्याज में।आधुनिक दुनिया में किसी भी राज्य की सुरक्षा भौतिक शक्ति से नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति से सुनिश्चित की जाती है

किसी भी तरह से ताकत, आर्थिक ताकत से उतनी ही जितनी सशस्त्र ताकत से।इसलिए यह तर्क देना व्यर्थ है कि कोफेपोसा का राज्य की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है।वास्तव में अधिनियम की प्रस्तावना में संसद ने कहा है कि विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन और तस्करी गतिविधियों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ता हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है जिससे राज्य की सुरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।जो भी हो, इस तर्क को आगे बढ़ाना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम कुल मिलाकर हैं।

भारत संघ बनाम में विकसित दृष्टिकोण के साथ समझौता।एच. ई. एस. ढिले

एकल, [1972] 2 एस. सी. आर. 33-सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा एक निर्णय।उक्त निर्णय में विकसित परीक्षण संक्षेप में यह हैःजहाँ किसी विशेष क़ानून को लागू करने के लिए संसद की विधायी क्षमता पर सवाल उठाया जाता है, वहाँ यह पता लगाने के लिए (इस संबंध में प्रसिद्ध सिद्धांतों को लागू करने के लिए) सूची-II में कई प्रविष्टियों को देखना चाहिए कि क्या उक्त क़ानून उन प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित है।यदि कानून सूची-II में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है, तो आगे की जांच की आवश्यकता नहीं है।यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि संसद उस क़ानून को अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, चाहे वह सूची-I और सूची-III में प्रविष्टियों के आधार पर हो या सूची-I की प्रविष्टि 97 के साथ पठित अनुच्छेद 248 के आधार पर हो।इस मामले में, यह भी सुझाव नहीं दिया जाता है कि विचाराधीन दोनों अधिनियमों में से कोई भी सूची-II में किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है।यदि ऐसा है, तो हमें आगे जी जाने और यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि ये अधिनियम किस प्रविष्टि या प्रविष्टियों से संबंधित हैं।यह माना जाना चाहिए कि संसद के पास उन्हें लागू करने की क्षमता थी।प्रश्न संख्या।2 और 3:ये सवाल इस तरह से उठते हैं।इसमें संबंधित निरोध के आदेश आपातकाल की घोषणा की तारीख को या उसके बाद दिए गए थे, जिस पर धारा 12-ए लागू थी।

एच. सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट [1994] में से कोई भी नहीं।.

24

ए वे हैं, जिन्हें हिरासत के 'सामान्य' आदेश कहा जा सकता है।इस कारण से, बंदियों को न तो हिरासत के आधार प्रदान किए गए थे, न ही उन्हें उनकी नजरबंदी के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया गया था और न ही ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मामलों को सलाहकार बोर्ड को भेजा गया था -

धारा 8 या उस मामले के लिए धारा 9 द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किसी भी दर पर नहीं।आपातकाल हटाए जाने की तारीख बी को या उसके एक या दो दिन के भीतर उन्हें रिहा कर दिया गया था।इस मायने में, निरोध का आदेश अपने आप काम कर गया है।लेकिन हिरासत के उस आदेश को अब आधार बनाया जा रहा है, जो हिरासत में लिए गए लोगों, उनके रिश्तेदारों और उनके सहयोगियों के खिलाफ SAFEMA के तहत कार्रवाई करने का आधार है।सी उप-धारा (2) के खंड (सी), (डी) और (ई) के साथ पठित धारा 2 (2) (बी) के आधार पर उनके लिए सेफेमा लागू किया जाता है।याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चूंकि कोफेपोसा के तहत हिरासत के आदेश को उनके खिलाफ सेफेमा के तहत कार्रवाई का आधार बनाया गया है,

वे निरोध के आदेश की वैधता को चुनौती देने के हकदार हैं।हो सकता है कि वे कोफेपोसा की धारा 12-ए (आधारों की गैर-आपूर्ति और सलाहकार बोर्ड को गैर-संदर्भ) के आधार पर अपनी नजरबंदी के दौरान निरोध की वैधता पर सवाल नहीं उठा पाए हों और यह भी कि अनुच्छेद 14,21 और 22 द्वारा उन्हें गारंटी दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत में जाने का उनका अधिकार आपातकाल की अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 359 (1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया था-यहां तक कि अनुच्छेद 19 ने भी अनुच्छेद 358 के आधार पर उनका लाभ नहीं उठाया-लेकिन जब निरोध के उक्त आदेशों को निम्नलिखित कार्रवाई का आधार बनाने की मांग की जाती है।

ई सेफेमा, आपातकाल हटाए जाने के बाद, वे अब उनसे सवाल करने के हकदार हैं।वे बताते हैं कि अनुच्छेद 359 (1) के तहत दिए गए आदेश के आधार पर, अनुच्छेद 14,21 और 22 द्वारा उन्हें दिए गए मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया गया था, बल्कि केवल उनके प्रवर्तन के लिए कदम उठाने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया था।यदि ऐसा है, तो वे कहते हैं कि उनके खिलाफ दिए गए निरोध आदेश अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) के उल्लंघन के लिए अमान्य और अवैध हैं।हो सकता है कि उन्हें राष्ट्रपति के उक्त आदेश के कारण अनुच्छेद 22,21 और 19 के तहत अपने अधिकारों को लागू करने से रोक दिया गया हो,

लेकिन यह निरोध के आदेशों को वैध नहीं बनाता था।वे कहते हैं कि इस तरह के अमान्य, वास्तव में अमान्य आदेश, SAFEMA के तहत कार्रवाई के आधार या आधार के रूप में काम नहीं कर सकते हैं।वे.

सेफेमा के प्रावधानों की कठोर प्रकृति पर भी जोर दिया जाता है।दूसरी ओर, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रावधानों पर निर्भर करता है

जी.

अनुच्छेद 359 का खंड (1 ए) और प्रस्तुत करता है कि उक्त निरोध आदेशों की वैधता का निर्णय कानून के संदर्भ में किया जाना चाहिए, न कि जारी करने की तारीख को प्राप्त कानून के संदर्भ में।

सेफेमा की धारा 6 के तहत नोटिस।किसी भी तरह से, वह प्रस्तुत करता है, अनुच्छेद 359 का खंड (1 ए) ऐसे सभी आदेशों को बचाता है।उपचार का निलंबन, वे कहते हैं कि एच अधिकार के निलंबन के समान है क्योंकि कोई एक की कल्पना नहीं कर सकता है

आई एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.] 25 बिना किसी उपचार के।उनका कहना है कि इस संबंध में अनुच्छेद ए 358 और अनुच्छेद 359 (1) के तहत एक आदेश के बीच कोई अंतर नहीं है।वह माखन सिंह बनाम में निर्णय के पृष्ठ 312 पर टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं।पंजाब राज्य, [1964] 4 एस. सी. आर. 797।

B संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को सशक्त बनाता है, यदि वह

इस बात से संतुष्ट कि एक गंभीर आपातकाल मौजूद है जिसके तहत भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा को खतरा है, चाहे वह युद्ध हो या बाहरी आक्रामकता या आंतरिक अशांति *, एक घोषणा द्वारा घोषणा करने के लिए कि आपातकाल मौजूद है। ऐसी घोषणा के परिणामों में से एक अनुच्छेद 358 में प्रदान किया गया है।अनुच्छेद 358, जैसा कि यह 44 वें संशोधन से पहले था, इस प्रकार पढ़ता है:358. जबकि आपातकाल की घोषणा लागू है, अनुच्छेद 19 में कुछ भी डी भाग III में परिभाषित राज्य की किसी भी कानून को बनाने या कोई कार्यकारी कार्रवाई करने की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगा, जो राज्य करेगा, लेकिन उस भाग में निहित प्रावधानों के लिए, लेकिन इस तरह बनाया गया कोई भी कानून, ई की सीमा तक सक्षम होगा।

अक्षमता, जैसे ही घोषणा का संचालन बंद हो जाता है, उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, सिवाय उन मामलों के जो कानून के समक्ष किए गए या किए जाने के लिए छोड़ दिए गए हैं, इसलिए उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है।

च

(संविधान 42 वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक परंतुक जोड़ा गया था और 44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ और संशोधन किए गए थे, लेकिन इन मामलों के प्रयोजनों के लिए उन्हें नोटिस करना आवश्यक नहीं है।)

अनुच्छेद 359 का खंड (1), जैसे कि 44 वें संशोधन से पहले था, जी ने प्रावधान किया कि "जहां आपातकाल की घोषणा लागू है, राष्ट्रपति आदेश द्वारा घोषणा कर सकता है कि भाग-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार जो आदेश में उल्लिखित हो और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में लंबित सभी कार्यवाही उस अवधि के लिए निलंबित रहेगी जिसके दौरान घोषणा लागू है या ऐसी छोटी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जा सकती है।"

अनुच्छेद 358 और 359 (1) का उद्देश्य और प्रभाव और उनके बीच का अंतर माखन सिंह के मामले में इस अदालत के विचार के लिए था।क.

विशेष-सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुच्छेद 358 के प्रभाव को निम्नलिखित शब्दों में बताया:

44 वें संशोधन अधिनियम द्वारा, "सशस्त्र विद्रोह" शब्दों को प्रतिस्थापित किया गया था

शब्द "आंतरिक गड़बड़ी"।

एल. आई.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस सी आर।

" यह ध्यान दिया जाएगा कि जैसे ही अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा जारी की गई है।352 और जब तक यह चलता है, कला।19 निलंबित किया जाता है और विधायिकाओं के साथ-साथ कार्यपालिका की शक्तियों को उस हद तक व्यापक बनाया जाता है।कला का निलंबन।19 आपातकाल की घोषणा के लंबित रहने के दौरान Art.19 द्वारा विधायी और कार्यकारी शक्तियों पर बनाई गई बाधाओं को हटा दिया जाता है और यदि विधायिकाएं कानून बनाती हैं या कार्यपालिका ऐसे कार्य करती है जो Art.19 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों के साथ असंगत हैं, तो उनकी वैधता को चुनौती देने के लिए या तो आपातकाल के जारी रहने के दौरान या उसके बाद भी खुला नहीं है।जैसे ही घोषणा का संचालन बंद हो जाता है, पारित किए गए विधायी अधिनियम और उक्त आपातकाल के दौरान की गई कार्यकारी कार्रवाइयां उस हद तक निष्क्रिय हो जाएंगी जिस हद तक वे Art.19 के तहत गारंटीकृत अधिकारों के साथ संघर्ष करती हैं क्योंकि जैसे ही आपातकाल हटा लिया जाता है, अनुच्छेद।19 जो आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया गया था, स्वचालित रूप से पुनर्जीवित हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है।हालांकि, अनुच्छेद 358 यह स्पष्ट करता है कि आपातकाल के दौरान किए गए या किए जाने वाले कार्यों को आपातकाल समाप्त होने के बाद भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।

क.

एस.

डी.

दूसरे शब्दों में, Art.19 का निलंबन विचाराधीन अवधि के दौरान पूरा हो जाता है और Art.19 का उल्लंघन करने वाली विधायी और कार्यकारी कार्रवाई पर आपातकाल के बाद भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

खत्म हो गया है "।

ई.

इसके बाद पीठ ने अनुच्छेद 359 (1) के अर्थ और उद्देश्य पर विचार किया।

और आयोजित किया गयाः

" दूसरी ओर, अनुच्छेद 359 स्पष्ट रूप से किसी भी मौलिक अधिकार को निलंबित करने का तात्पर्य नहीं रखता है।यह राष्ट्रपति को यह घोषणा करते हुए एक आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करता है कि आदेश में उल्लिखित भाग III में ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का अधिकार और इस प्रकार उल्लिखित अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में लंबित सभी कार्यवाही उस अवधि के लिए निलंबित रहेगी जिसके दौरान घोषणा लागू है या ऐसी छोटी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाए।राष्ट्रपति के आदेश का उद्देश्य राष्ट्रपति को Art.359 (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर जो करना है, वह नागरिकों के उपचार को निर्दिष्ट अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने से रोकना है।अधिकार स्पष्ट रूप से निलंबित नहीं हैं, लेकिन नागरिक को उनके प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने के अपने अधिकार से वंचित किया जाता है।यह Art.358 और कला के प्रावधानों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।359 (1) " .

च

जी.

27

एच. एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए "।ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी)।जे.]

विद्वान महान्यायवादी द्वारा यह आग्रह किया गया था कि किसी विशेष मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के नागरिक के अधिकार का निलंबन उक्त अवधि के लिए उक्त अधिकार को निलंबित करने के बराबर है।हालाँकि, पीठ ने

उक्त प्रश्न में जाने से इनकार कर दिया और इस धारणा पर आगे बढ़ी कि राष्ट्रपति के आदेश की अवधि के दौरान भी "उक्त अधिकार सिद्धांत रूप में जीवित हैं"।विशेष पीठ बी ने आगे बताया:

" यह ध्यान दिया जाएगा कि राष्ट्रपति का आदेश विधायिकाओं या कार्यपालिका के अधिकार का विस्तार नहीं कर सकता है; यह केवल इस आधार पर राहत प्राप्त करने के लिए किसी भी अदालत में जाने के अधिकारों को निलंबित करता है कि भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन किया गया है यदि उक्त अधिकार आदेश में निर्दिष्ट हैं।इस स्थिति का अपरिहार्य परिणाम यह है कि जैसे ही आदेश लागू होना बंद हो जाता है, विधायी अधिनियम या कार्यकारी कार्रवाई द्वारा किए गए अधिकारों के उल्लंघन को शायद एक नागरिक द्वारा अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उन पर इस आधार पर मुकदमा चलाया जा सकता है कि जिन अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, वे राष्ट्रपति के आदेश के लंबित रहने के दौरान भी लागू थे।यदि राष्ट्रपति के आदेश की समाप्ति पर, संसद राष्ट्रपति के आदेश के लंबित रहने के दौरान की गई कार्यकारी कार्रवाई की रक्षा के लिए कोई कानून पारित करती है और राष्ट्रपति के आदेश में कार्यपालिका को क्षतिपूर्ति प्रदान करती है।

एस.

डी.

इस ओर से, ऐसी विधायी कार्रवाई की वैधता और प्रभाव की सावधानीपूर्वक जांच की जा सकती है।

कला की आपत्ति के बाद से।359 (1) किसी भी अदालत में जाने के नागरिकों के अधिकारों को निलंबित करने के लिए, राष्ट्रपति के आदेश का परिणाम यह हो सकता है कि कोई भी कार्यवाही जो आदेश की तारीख तक लंबित हो सकती है, उस समय के दौरान निलंबित रहती है जब एफ आदेश लागू होता है और जब उक्त आदेश लागू नहीं होता है तो इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है; और आदेश जारी होने के बाद किसी नागरिक द्वारा नई कार्यवाही नहीं की जा सकती है, क्योंकि आदेश किसी भी अदालत में जाने का अधिकार छीन लेता है और आदेश के संचालन के दौरान, आदेश के विपरीत एक नई जी कार्यवाही शुरू करके उक्त अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।यदि Art.359 (1) की शरारत के अंतर्गत आने वाली कोई नई कार्यवाही और इसके तहत जारी राष्ट्रपति का आदेश आदेश जारी होने के बाद शुरू किया जाता है, तो इसे अक्षम होने के कारण खारिज करना होगा।दूसरे शब्दों में, कला।359 (1) और इसके तहत जारी राष्ट्रपति का आदेश एक प्रकार का गठन कर सकता है

स्थगन या संस्था के खिलाफ पूर्ण प्रतिबंध या समझौता एच 28

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. दो महत्वपूर्ण शर्तों के अधीन किसी भी कानूनी कार्रवाई का एक क्रम।पहली शर्त कानूनी कार्रवाई के स्वरूप से संबंधित है और यह आवश्यक है कि उक्त कार्रवाई को इस आधार पर राहत प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए कि दावेदार के राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, और दूसरी शर्त

4 1

यह उस अवधि से संबंधित है जिसके दौरान यह प्रतिबंध लागू होना है।द.

प्रतिबंध या तो घोषणा की अवधि के लिए या आदेश में निर्दिष्ट की गई छोटी अवधि के लिए लागू होता है।

विशेष पीठ द्वारा प्रतिपादित कानून स्पष्ट और स्पष्ट है।इसे हमारे हाथों में विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

एस.

उक्त निर्णय के बाद, हालांकि, खंड (1 ए) में पेश किया गया था

संविधान 38 वां (संशोधन) अधिनियम, 1975 द्वारा अनुच्छेद 359।इस खंड को संविधान की तारीख से पुनर्निर्धारित प्रभाव के साथ पेश किया गया था।खंड (1 ए), जैसा कि उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, निम्नानुसार है:1 ए.जबकि खंड (1) के अधीन किए गए आदेश में से किसी का उल्लेख किया गया है -

डी.

भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकार लागू हैं, उन अधिकारों को प्रदान करने वाले उस भाग में कुछ भी राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगा

}

उक्त भाग में ऐसी कोई विधि बनाने या कोई ऐसी कार्यपालक कार्रवाई करने के लिए परिभाषित किया गया है जिसे राज्य उस भाग में निहित प्रावधानों के अलावा करने या करने के लिए सक्षम होगा, लेकिन इस प्रकार बनाई गई कोई विधि, अक्षमता की सीमा तक, जैसे ही पूर्वोक्त आदेश का संचालन बंद हो जाता है, प्रभावी नहीं होगी, सिवाय उन चीजों के जो कानून के समक्ष की गई या की जाने के लिए छोड़ी गई हैं, जिनका प्रभाव समाप्त हो जाता हैः

ई.

42 वें संशोधन अधिनियम, एफ 1976 द्वारा इस खंड में निम्नलिखित प्रभाव से एक परंतुक जोड़ा गया थाः

" बशर्ते कि जहां आपातकाल की घोषणा केवल भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में लागू है, वहां इस अनुच्छेद के तहत ऐसी कोई कानून बनाई जा सकती है, या ऐसी कोई कार्यकारी कार्रवाई की जा सकती है, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में या जिसमें या किसी ऐसे हिस्से में जिसमें आपातकाल की घोषणा लागू नहीं है।

जी.

यदि और जहाँ तक भारत या उसके क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा को भारत के क्षेत्र के उस हिस्से में या उसके संबंध में गतिविधियों से खतरा है जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई है।

संचालन में "।

एच.

(44 वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा, "अनुच्छेद 20 अटॉर्नी जनरल को छोड़कर" शब्द।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.] 29 और 21 "को खंड (1 बी) जोड़ने के अलावा खंड (1 ए) में" भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकार "शब्दों के बाद जोड़ा गया था, लेकिन ये संशोधन, जो पूर्वव्यापी नहीं हैं, हिरासत के मामले में प्रासंगिक नहीं हैं।

उद्भव की अवधि के दौरान कोफेपोसा की धारा 12-ए द्वारा शासित

सी.)

यह स्पष्ट है कि खंड (1 ए) को अनुच्छेद 359 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के प्रभाव को अनुच्छेद 358 (1) के बराबर लाने की दृष्टि से रखा गया था, जहां तक निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कानून बनाने की राज्य की क्षमता का संबंध है। अनुच्छेद 359 (1 ए) मोटे तौर पर अनुच्छेद 358 के समान है।अनुच्छेद 358 में कहा गया है कि

अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा लागू है "अनुच्छेद 19 में कुछ भी राज्य की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करेगा जैसा कि भाग-3 में परिभाषित किया गया है, कोई कानून बनाने या कोई कार्यकारी कार्रवाई करने के लिए जो राज्य उस भाग में निहित प्रावधानों के अलावा करने या करने के लिए सक्षम होगा, लेकिन इस तरह से बनाई गई कोई भी कानून अक्षमता की सीमा तक प्रभावी नहीं होगी, जैसे ही घोषणा का संचालन बंद हो जाता है, सिवाय उन चीजों के जो कानून के प्रभाव में आने से पहले की गई या छोड़ी गई थीं।"इसी प्रकार अनुच्छेद 359 के खंड डी (1 ए) में कहा गया है कि जबकि अनुच्छेद 359 (1) के तहत बनाया गया राष्ट्रपति का आदेश लागू है, "उस भाग (भाग-3) में कुछ भी नहीं है जो यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अधिकार उक्त भाग में परिभाषित राज्य की किसी भी कानून को बनाने या किसी भी कार्यकारी कार्रवाई को करने की शक्ति को प्रतिबंधित करेंगे, जिसे राज्य उस भाग में निहित प्रावधानों के अलावा करने या लेने के लिए सक्षम होगा, लेकिन अक्षमता की सीमा तक इस तरह बनाया गया कोई भी कानून, जैसे ही उपरोक्त आदेश का संचालन बंद हो जाता है, प्रभावी नहीं होगा, सिवाय उन चीजों के जो कानून के समक्ष की गई या की जाने के लिए छोड़ी गई थीं।बेशक, जबकि अनुच्छेद 358 केवल अनुच्छेद 19 तक ही सीमित है, खंड (1 ए) उन अधिकारों तक फैला हुआ है जिनके प्रवर्तन को अनुच्छेद 359 (1) के तहत एक आदेश द्वारा निलंबित किया

गया हो सकता है।दूसरा अंतर यह है कि अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 का एफ "निलंबन" * आपातकाल की घोषणा की अवधि के साथ सह-व्यापक है, खंड (1 ए) उस अवधि तक सीमित है जिसके लिए राष्ट्रपति का आदेश लागू रहता है।एक और।

अंतर यह है कि जहां अनुच्छेद 358 राज्य को आपातकाल की अवधि के दौरान कोई भी कानून बनाने या अनुच्छेद 19 के साथ असंगत कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है, वहीं अनुच्छेद 359 के खंड (1) और (1 ए) को एक साथ पढ़ने पर जी को राष्ट्रपति के आदेश के प्रवर्तन के निलंबन (राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से) के लिए प्रदान करता है।

आदेश में निर्दिष्ट मौलिक अधिकार और साथ ही सक्षम करते हैं

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल अनुच्छेद 358 का शीर्षक "के निलंबन" की बात करता है।

अनुच्छेद 19 के प्रावधान; * अनुच्छेद के मुख्य भाग में निलंबन का कोई संदर्भ नहीं है।

एच.

लेख से।

> सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस सी आर।

30

क. राज्य को कोई कानून बनाना या ऐसे मौलिक अधिकारों के साथ असंगत कोई कार्यकारी कार्रवाई करना।यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 358 (अनुच्छेद 19 के साथ असंगत कानून बनाने या कार्यकारी कार्रवाई करने के लिए राज्य की क्षमता) के संबंध में माखन सिंह में जो कहा गया है, वह पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ खंड (1 ए) की शुरूआत के आधार पर अनुच्छेद 359 पर समान रूप से लागू होता है।दूसरे शब्दों में, इस अवधि के दौरान राष्ट्रपति के आदेश के तहत

बी अनुच्छेद 359 (1) लागू है, राज्य कोई भी कानून बनाने या कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने के लिए सक्षम है जो वह राष्ट्रपति के आदेश में निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन के अलावा नहीं कर सकता था।हमारी राय में, अनुच्छेद 358 के तहत स्थिति यह हैःअनुच्छेद 358 राज्य को कोई भी कानून बनाने या अनुच्छेद 19 के साथ असंगत कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने में सक्षम बनाता है।यह असाधारण शक्ति है,

एस.

हालाँकि, यह आपातकाल की अवधि तक ही सीमित है और इसका उद्देश्य आपातकाल के उद्देश्यों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना है।इस असाधारण प्रावधान का औचित्य यह है कि अनुच्छेद के अर्थ के भीतर भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा के लिए खतरे का सामना करने के लिए आवश्यक पाए जाने पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को अस्थायी रूप से स्थगित करना पड़ सकता है।

डी 352 (1)।जैसे ही आपातकाल समाप्त हो जाता है, इस प्रकार बनाया गया कानून अनुच्छेद 19 के साथ असंगति की सीमा तक प्रभावी नहीं होगा, सिवाय उन चीजों के जो कानून के समक्ष की गई या की जाने वाली चीजों के संबंध में प्रभावी नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि आपातकाल की अवधि के दौरान उक्त अनुच्छेद के आधार पर बनाए गए कानून की वैधता या किए गए कार्यों या किए जाने वाले कार्यों को अनुच्छेद 19 के साथ असंगति के आधार पर आपातकाल के दौरान या उसके बाद सवाल नहीं उठाया जा सकता है।न तो कानून और न ही कार्यकारी कार्रवाई (अनुच्छेद 19 के साथ इसकी विसंगति की सीमा तक) आपातकाल की समाप्ति के बाद एक दिन के लिए भी जारी नहीं रह सकती है।हालाँकि, उनकी वैधता और/या आपात स्थिति की अवधि के दौरान उन्हें बनाने या लेने की राज्य की क्षमता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।दृष्टांत के माध्यम से एक कानून बनाया गया हो सकता है या एक कार्यकारी कार्रवाई अनुचित रूप से की गई हो सकती है।

च

भाषण की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करना

आपात स्थिति।इस तरह का प्रतिबंध जहां तक अनुच्छेद 19 (2) द्वारा आवश्यक नहीं है, आपातकाल की समाप्ति के साथ काम करना या प्रभावी होना बंद कर देता है।लेकिन जिस नागरिक के अधिकार में अनुचित रूप से कटौती की गई है, वह राज्य पर

हर्जाने या अन्य राहत के लिए मुकदमा नहीं कर सकता है और न ही वह आपातकाल की अवधि के दौरान इस तरह के अनुचित प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य के खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही कर सकता है।ऐसा अनुच्छेद 358 द्वारा राज्य को प्रदान किए गए संरक्षण के कारण है।यह याद रखना चाहिए कि अनुच्छेद 358 इस तरह के पाठ्यक्रम को प्रतिबंधित करता है क्योंकि संस्थापक पिता ने सोचा था-और बिना किसी औचित्य के-कि जब भारत या उसके किसी भी हिस्से की सुरक्षा

अनुच्छेद 352 द्वारा परिकल्पित खतरे के रूप में, राज्य को स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए

एच. एटॉर्नी जनरल, भारत के लिए बनाम।ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.] 31 ऐसा कानून बनाते हैं या ऐसी कार्यकारी कार्रवाई करते हैं जो अनुच्छेद 19 के प्रावधानों से मुक्त देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।यह

हालाँकि, अनुच्छेद 19 का अधीनता केवल उस अवधि के लिए है जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा लागू होती है।

अब अनुच्छेद 359 के खंड (1) और (1 ए) पर आते हुए स्थिति बी यह हैःजबकि खंड (1) राष्ट्रपति को ऐसी अधिसूचना में नामित मौलिक अधिकारों (और किसी भी अदालत में उस ओर से कोई भी और सभी कार्यवाही) के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार देता है, यह राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने का अधिकार नहीं देता है।जाहिर है, संस्थापक पिताओं ने राष्ट्रपति को इस तरह की शक्ति पहनना आवश्यक नहीं समझा।खंड (1) के शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं।वे केवल भाग-III में अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने और स्वयं के अधिकारों को निलंबित नहीं करने की बात करते हैं।हम कोई वारंट, कोई औचित्य और यह मानने का कोई आधार नहीं देखते हैं कि अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का मतलब प्रभावी रूप से अधिकारों का निलंबन है।यदि संस्थापक पिताओं का यही इरादा होता, तो वे ऐसा स्पष्ट रूप से कहते।वास्तव में, उन्होंने स्पष्ट भाषा में बताया है कि डी का क्या अर्थ है।इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भाग-III में मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति के आदेश से प्रभावित होने की अनुमति है, हम सोचते हैं कि हमें खंड में स्पष्ट रूप से जो कहा गया है उससे अधिक कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए-और इसकी भाषा किसी भी संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है।यह माखन सिंह (साथ ही भगवती, जे. द्वारा ए. डी. एम. जबलपुर बनाम.) में लिया गया दृष्टिकोण है।शिवकांत शुक्ला, [1976] 2 एस. सी. सी. 521 719 पर।पारस 479 और 480] और हम सम्मानपूर्वक उनसे सहमत हैं।इसके बाद खंड (1 ए) आया, जिसे संविधान की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ 38 वें संशोधन अधिनियम द्वारा पेश किया गया।इसमें कहा गया है कि जब विशेष मौलिक अधिकारों को निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश लागू है, तो राज्य को कोई भी कानून बनाने या कोई भी कानून बनाने का अधिकार होगा।

कार्यकारी कार्रवाई जो वह एफ करने या लेने का हकदार नहीं होता, लेकिन उक्त अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन के लिए।साथ ही, खंड में कहा गया है कि इस प्रकार बनाया गया कोई भी कानून, राष्ट्रपति के आदेश के लागू होने के तुरंत बाद, अप्रभावी होने की सीमा तक प्रभावी नहीं होगा, सिवाय उन मामलों के जो कानून के समक्ष किए गए या किए जाने के लिए छोड़ दिए गए थे।इन शब्दों का प्रभाव ("जी को छोड़कर)

सम्मान. प्रभाव) स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 358 (जो भी समान शब्दों का उपयोग करता है) के तहत प्राप्त करने के समान है जिसे हमने पहले कुछ विस्तार से समझाया है।यह सच है कि अनुच्छेद 359 का खंड (1) किसी भी मौलिक अधिकार के निलंबन का प्रावधान नहीं करता है, बल्कि केवल उनके प्रवर्तन का प्रावधान करता है और यह भी उतना ही सच है कि वे मौलिक अधिकार (जिनके प्रवर्तन को निलंबित कर दिया गया है) सिद्धांत रूप में जीवित हैं, फिर भी हमें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] का भी समर्थन करना चाहिए।

1 एस सी आर।

32

खंड (1 ए) का प्रभाव, जो अब समान रूप से अनुच्छेद 359 का एक हिस्सा है-और 26 जनवरी, 1950 से शुरू होने वाले सभी समय पर ऐसा हिस्सा माना जाना चाहिए।इसलिए यह निष्कर्ष अपरिहार्य है कि अनुच्छेद 359 (1) के तहत भाग-3 द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने वाला राष्ट्रपति का आदेश लागू होने की अवधि के दौरान, राज्य को कोई भी कानून बनाने या कोई भी कार्यकारी कार्रवाई करने का अधिकार है।

ऐसे अधिकारों के साथ।यह सब इसलिए है क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए खतरे से निपटने के लिए घोषित आपातकाल को प्रभावी ढंग से लागू करना होगा।आपातकाल की आवश्यकताएँ आधार के साथ-साथ शक्ति पर एक निहित सीमा दोनों का गठन करती हैं।आपातकाल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो आवश्यक है वह आवश्यक है।

एस.

इस समय कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उचित हो सकता है -

यह न्यायालय इस संबंध में प्रासंगिक है।जयचंद लाल में, वी।पश्चिम बंगाल राज्य, [1966] सुपल।एस. सी. आर. 464, यह एक संविधान पीठ द्वारा अभिनिर्धारित किया गया हैः

" लेकिन अपीलार्थी आदेश की वैधता को चुनौती दे सकता है

डी.

" कला द्वारा कवर किए गए मैदानों के अलावा अन्य।358 , या कला के तहत जारी राष्ट्रपति का आदेश।359 (1) .इस तरह की चुनौती राष्ट्रपति के आदेश के दायरे से बाहर है।उदाहरण के लिए, एक नागरिक को इस आधार पर बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए एक उपयुक्त अदालत में जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा कि उसकी नजरबंदी का आदेश दुर्भावनापूर्ण तरीके से दिया गया है।इसी तरह, नागरिक इस आधार पर निरोध के आदेश को चुनौती दे सकता है कि निरोध के आदेश में दिया गया कोई भी आधार अप्रासंगिक है और दिए गए आधार और विधायिका के विचार में उद्देश्य के बीच कोई वास्तविक और निकट संबंध नहीं है।इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सत्ता का दुर्भावनापूर्ण प्रयोग आवश्यक रूप से कानून के मामले में किसी भी नैतिक पतन का संकेत नहीं देता है।इसका केवल यह अर्थ है कि वैधानिक शक्ति का प्रयोग उन उद्देश्यों के लिए किया जाता है जो उनके लिए विदेशी हैं जिनके लिए यह कानून में अभिप्रेत है।दूसरे शब्दों में, क़ानून द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए किया गया है जो क़ानून के उद्देश्य या उस शरारत से जुड़ा नहीं है जिसे वह दूर करना चाहता है।

ई.

च

?

जी.

आनंदन नांबियार बनाम मामले में एक अन्य संविधान पीठ का निर्णय भी इसी प्रभाव का है।मुख्य सचिव, मद्रास सरकार, [1966] 2 S.C.R.406।ए. डी. एम., जबलपुर में बहुमत की राय, हालांकि, एच को जयचंद लाल और आनंदन अटॉर्नी जनरल में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण के विपरीत प्रतीत होती है।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.) 33 नाम्बियार लेकिन इस मामले के उद्देश्यों के लिए ए. डी. एम. जबलपुर में तर्क की शुद्धता में जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यह नहीं किया गया है

हमारे सामने चर्चा की।वास्तव में, भारत संघ में तीन न्यायाधीशों की पीठ बनाम।

भानुदास कृष्ण गावडे, [1977] 2 एस. सी. सी. 719 ने ए. डी. एम., जबलपुर का पालन करते हुए चरम दृष्टिकोण अपनाया है कि अनुच्छेद 359 (1) के तहत बी आदेश लागू होने की अवधि के दौरान अदालत में लगाए गए प्रतिबंधों और सुविधाओं से इनकार पर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता है!

अगला मुद्दा यह उठता है कि क्या आपातकाल के दौरान पारित निरोध आदेशों के मामले में यह कहा जा सकता है (यानी, निरोध के आदेश जिन पर कोफेपोसा की धारा 12-ए लागू होती है) कि वे अमान्य हैं या अप्रमाणित हैं, ताकि उन्हें सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के अर्थ सी के भीतर निरोध के आदेश के रूप में नहीं माना जा सके?विद्वत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आदेशों को शुरुआत से ही अमान्य या अमान्य नहीं कहा जा सकता है।आदेश अच्छे और वैध थे जब वे कोफेपोसा की धारा 3 के तहत बनाए गए थे।वे कहते हैं, हो सकता है कि राष्ट्रपति के आदेश की समाप्ति के साथ उक्त आदेशों का संचालन बंद हो गया हो और उक्त समाप्ति के बाद भी जारी नहीं रखा जा सकता हो, लेकिन जब वे बनाए गए थे तो वे निश्चित रूप से सक्षम, कानूनी और प्रभावी थे और राष्ट्रपति के आदेश की समाप्ति तक ऐसे ही बने रहे।इसलिए, उन्हें निश्चित रूप से सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के उद्देश्य और अर्थ के भीतर कोफेपोसा के तहत हिरासत के आदेश के रूप में माना जा सकता है।

आई.

ई.

दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का तर्क है कि कोफेपोसा की धारा 12-ए के साथ पठित धारा 3 के तहत किया गया निरोध का आदेश अनुच्छेद 22 के प्रावधानों के साथ असंगत होने के कारण अमान्य है, जिन्हें निलंबित नहीं किया गया था। उक्त अनुच्छेद के प्रवर्तन का केवल निलंबन अधिकार का निलंबन नहीं है।अतः एफ निरोध के आदेश अमान्य थे और वे केवल इसलिए लागू रहे क्योंकि राष्ट्रपति के आदेश के तहत लगाए गए प्रतिबंध के कारण बंदियों को उक्त आदेशों की वैधता पर सवाल उठाने से रोक दिया गया था।

अनुच्छेद 359 (1)।वे प्रस्तुत करते हैं कि कोफेपोसा की धारा 12-ए द्वारा शासित निरोध आदेश स्वाभाविक रूप से मनमाने और अन्यायपूर्ण हैं।जी निवारक निरोध का आदेश उसकी नजरबंदी के आधार के बारे में बताए बिना और उसे प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिए बिना किया जाता है।यहाँ तक कि उसके मामले पर विचार करने का संरक्षण भी।एक स्वतंत्र निकाय (सलाहकार बोर्ड) द्वारा ले लिया जाता है।बंदी पूरी तरह से असहाय हो जाता है।उसके पास कोई उपाय नहीं बचा है।वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता।निरोध का ऐसा आदेश एच 1 की सभी अवधारणाओं के खिलाफ है।

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस सी आर।

34

निष्पक्षता, सभ्य आचरण और लोकतांत्रिक मानदंड।वे प्रस्तुत करते हैं कि इस तरह के आदेश उनके लिए सेफेमा को लागू करने के लिए आधार या आधार नहीं बना सकते हैं।उनका तर्क न्यायमूर्ति कार्डोजो ने एक बार जो कहा था, उसे उजागर करता हैः "हमें हमेशा ऑपर ट्यूनिज्म के हमलों, बीतते समय की सहजता, छोटे अतिक्रमणों के क्षरण और धैर्य न रखने वालों के तिरस्कार और उपहास के खिलाफ कानून की रक्षा के लिए ध्यान रखना चाहिए।

सामान्य सिद्धांतों के साथ "।ऊपर बताए गए परस्पर विरोधी दृष्टिकोण दो प्रकारों को जन्म देते हैं -

सोचा।एक विचार इस प्रकार हैःअनुच्छेद 359 के खंड (1 ए) के आधार पर, संविधान 38 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा पूर्वव्यापी सी प्रभाव के साथ जोड़ा गया।धारा 12-ए को सक्षम रूप से अधिनियमित माना जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह राष्ट्रपति के आदेश की अवधि तक सीमित है।यदि ऐसा है, तो उसके तहत हिरासत को अमान्य नहीं कहा जा सकता है। जबकि निरोध का आदेश निश्चित रूप से राष्ट्रपति के आदेश की समाप्ति से परे नहीं रह सकता है क्योंकि धारा 12-ए स्वयं प्रत्येक डी समाप्ति से परे नहीं रह सकती है, न तो धारा 12-ए और न ही इसके द्वारा शासित निरोध के आदेश को उस अवधि के दौरान अवैध या अमान्य के रूप में वर्णित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति का आदेश लागू था।एक बार ऐसा होने पर, निरोध का ऐसा आदेश निस्संदेह सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के अर्थ और चिंतन के भीतर निरोध के आदेश का प्रतिनिधित्व करता है।यह कि यह राष्ट्रपति के आदेश की अवधि के दौरान चुनौती देने के लिए खुला नहीं था, या यह कि यह अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं था, इसकी वैधता या वैधता को प्रभावित नहीं करता है।यह हिरासत में लेने का एक वैध आदेश था।इसे राष्ट्रपति के आदेश की अवधि के बाद लागू या कार्रवाई नहीं की जा रही है।चूंकि यह एक मौजूदा तथ्य है, इसलिए इस पर केवल ध्यान दिया जा रहा है-और यह ऐसे बंदी, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के प्रति SAFEMA को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है।एफ. सेफेमा की धारा 2 (1) में कहा गया है, "इस अधिनियम के प्रावधान केवल उप-धारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर लागू होंगे" और उप-धारा (2) अन्य बातों के साथ-साथ उस व्यक्ति के बारे में बात करती है जिसके संबंध में कोफेपोसा, 1974 के तहत निरोध का आदेश दिया गया है।वास्तव में, खंड के प्रावधान (i), (ii) और (iii)

(बी) सेफेमा की धारा 2 की उप-धारा (2) का स्पष्ट रूप से धारा 12-ए के तहत किए गए निरोध के आदेश का उल्लेख करता है और स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है कि

निरोध का जी आदेश उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निरोध का एक आदेश है।तथ्य यह है कि सेफेमा के प्रावधानों को पहली बार 5 नवंबर, 1975 को जारी एक अध्यादेश के रूप में अधिनियमित किया गया था, यानी आपातकाल की अवधि के दौरान और बाद में एक अधिनियम में अधिनियमित किया गया और अध्यादेश की तारीख से प्रभावी किया गया।इसलिए, कोफेपोसा की धारा एच 12-ए द्वारा शासित निरोध के आदेश को सामान्य रूप से निरोध का आदेश माना जाना चाहिए।

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी, जे. जे. 35 सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के उद्देश्य के लिए और उसके अर्थ के भीतर।ए तर्क की दूसरी पंक्ति निम्नलिखित पंक्तियों के साथ जाती है धारा 12-ए द्वारा शासित निरोध का आदेश आपातकाल से प्रभावी ढंग से निपटने के सीमित उद्देश्य के लिए बनाया गया एक विशेष प्रकार का आदेश है।उक्त सीमित उद्देश्य के अलावा इसका कोई अस्तित्व, प्रासंगिकता या प्रभाव नहीं है।इस तरह के उद्देश्य के बाहर, यह गैर-अनुमानित है।इसका अस्तित्व नहीं है।यदि ऐसा है, तो निरोध का ऐसा आदेश बी

SAFEMA को लागू करने के लिए आधार, कनेक्टिंग लिंक या आधार प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।निवारक निरोध का एक सामान्य आदेश अपने आप में एक असभ्य कार्रवाई है।कोफेपोसा की धारा 12-ए द्वारा शासित निरोध का आदेश-अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (5) द्वारा प्रदान किए गए न्यूनतम सुरक्षा उपायों को भी अस्वीकार करना एक घृणित कार्रवाई है।इसे एक क्रूर आवश्यकता के रूप में बर्दाश्त किया जा सकता है जब राष्ट्र का जीवन ही खतरे में हो, लेकिन इसे निश्चित रूप से किसी अन्य उद्देश्य के लिए मान्यता या ध्यान नहीं दिया जा सकता है-बहुत कम SAFEMA जैसे अत्यंत कठोर अधिनियम को लागू करने का आधार बनाया गया है।Y ऐसे निरोध के आदेश को SAFEMA की धारा 2 (2) (b) के उद्देश्य के लिए और उसके अर्थ के भीतर निरोध के आदेश के रूप में मानना, D के बाहर और बाहर निरोध के उक्त आदेश को लागू करने या प्रभावी करने के बराबर है।

}

आपातकाल की अवधि और विदेशी से लेकर आपातकाल तक के उद्देश्यों के लिए।यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।धारा 12-ए इसे मंजूरी नहीं देती है-हालाँकि यह बहुत सी चीजों को प्रतिबंधित करती है।

जबकि हम तर्क के साथ-साथ विचार की दूसरी पंक्ति की भावनात्मक अपील से आकर्षित होते हैं, यह स्वतंत्रता के किसी भी प्रेमी को आकर्षित करेगा-हम खुद को इसे अस्वीकार करने के लिए विवश पाते हैं क्योंकि SAFEMA की धारा 2 (2) (b) की भाषा इस तथ्य के साथ जुड़ी हुई है कि SAFEMA IX वीं अनुसूची के साथ पठित अनुच्छेद 31-B की सुरक्षात्मक छत्रछाया से लैस है।हम विस्तार से आगे बढ़ते हैं।सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) में स्पष्ट रूप से निरोध का एक आदेश शामिल है जिस पर धारा 12-ए के प्रावधान कोफेपोसा के तहत निरोध के आदेश के दायरे में लागू होते हैं।के लिए

ई.

च

संदर्भ की सुविधा के लिए, हम खंड को पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।इसमें लिखा हैः

" (ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण के तहत निरोध का आदेश दिया गया है और

तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 (1974 का 52):जी ने प्रावधान किया कि

((i) निरोध का ऐसा आदेश, एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12-ए के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, सलाहकार एच 36 की रिपोर्ट पर रद्द नहीं किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत या रसीद से पहले एस. सी. आर. बोर्ड

क.

सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट या सलाहकार बोर्ड को संदर्भ देने से पहले; या

एल.

((ख) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा (9) के प्रावधान लागू होते हैं,

धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत समीक्षा के लिए या उसके आधार पर समय समाप्त होने से पहले या

न.

उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट; या

((ग) निरोध का ऐसा आदेश, जिसके लिए -

एस.

उक्त अधिनियम की धारा 12-ए के प्रावधान लागू होते हैं, उस धारा की उप-धारा (3) के तहत पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर या उस अधिनियम की धारा 12-ए की उप-धारा (6) के साथ पठित धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर समय समाप्त होने से पहले रद्द नहीं किया गया है; या

:1

डी.

((iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत द्वारा रद्द नहीं किया गया है।

प्रावधान (iii) स्पष्ट रूप से "एक आदेश (निरोध का) जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12-ए के प्रावधान लागू होते हैं" और जिसे "लागू नहीं किया गया है।

ई.

समय की समाप्ति से पहले उस धारा (धारा 12-ए) की उप-धारा (3) के तहत पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर या उस अधिनियम की धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर, जिसे धारा 12-ए की उप-धारा (6) के साथ पढ़ा जाता है, उस अधिनियम की धारा 2 (2) के खंड (बी) के उद्देश्य के लिए और उसके अर्थ के भीतर निरोध के आदेश के रूप में निरस्त कर दिया गया।एफ के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सेफमा के साथ-साथ कोफेपोसा को नौवें में शामिल किया गया है।

संविधान के 39 वें और 40 वें (संशोधन) अधिनियमों की अनुसूची, सेफेमा की धारा 2 (2) का खंड (बी) (इससे जुड़े परंतुक (iii) सहित) संवैधानिक निंदा से परे हैं।एक को उक्त लेना होगा

प्रावधान जैसा कि वे खड़े हैं और वे याचिकाकर्ताओं की दलीलों के खिलाफ दृढ़ता से खड़े हैं।इस एकल आधार पर, हम मानते हैं, जैसा कि हमें करना चाहिए, कि एक आदेश

जी.

कोफेपोसा के तहत किया गया निरोध, जिसके लिए धारा में प्रावधान हैं

12 - ए लागू किया गया, सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के अर्थ के भीतर और उसके उद्देश्यों के लिए निरोध का एक आदेश है और इसलिए, ऐसे व्यक्ति पर सेफेमा लागू करने के लिए आधार का गठन कर सकता है।

इस समय दो निर्णयों से निपटना उचित होगा डी

एच.

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.इस न्यायालय के ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.] 37 ने हमारे संज्ञान में लाया।पहला भारत संघ बनाम में है।ए. हाजी मस्तान मिर्जा, [1984] 3 एस. सी. आर. 1 तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसमें प्रतिवादी को पहले आंतरिक रखरखाव के तहत हिरासत में लिया गया था।

17 सितंबर, 1974 के एक आदेश के तहत सुरक्षा अधिनियम (M.I.S.A.)।19 दिसंबर, 1974 को उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन साथ ही कोफेपोसा की धारा 3 (1) के तहत हिरासत का आदेश दिया गया था।मैदान।

23 दिसंबर, 1974 को उन्हें हिरासत में रखा गया था।25 जून, 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर अनुच्छेद 352 (1) के तहत आपातकाल घोषित किया गया था, जो 21 मार्च, 1977 तक लागू रहा।रेस्पॉन डेंट 23 मार्च, 1977 को जारी किया गया था।नोटिस करें।सेफेमा की धारा 6 (1) के तहत उन्हें, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों को जारी किया गया था, जहां

उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में इस आधार पर 19 दिसंबर, 1974 के निरोध के आदेश सी की वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी कि उन्हें आवश्यक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए दस्तावेजों के साथ स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से भरोसा नहीं किया गया था और उन्हें दिए गए निरोध के आधार पर किन दस्तावेजों का भी उल्लेख किया गया था।बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिट याचिका को मंजूरी दे दी, जिसके खिलाफ यूनियन ऑफ डी.

भारत ने इस अदालत में अपील की।न्यायाधीश वरदराजन ने पीठ की ओर से बोलते हुए सेफेमा की धारा 2,6 और 7 के प्रावधानों का उल्लेख किया और कहा

इस प्रकारः

" इसलिए, कोफेपोसा के तहत हिरासत का एक वैध आदेश है

एस. एस. के तहत की जा रही कार्यवाही के लिए पूर्ववर्ती शर्त।6 और सेफेमा का 7 ई।यदि किसी भी कारण से 10.12.1974 दिनांकित निरोध के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है, तो एस. एस. के तहत कार्यवाही की जाती है।6 और SAFEMA का 7 खड़ा नहीं हो सकता है।इसलिए, हमें विचार करना होगा

क्या हिरासत का विवादित आदेश दिनांक 19.12.1974 के तहत है

कोफेपोसा अमान्य है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

च

ऊपर बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि हिरासत का आदेश 25 जून, 1975 को आपातकाल की घोषणा से बहुत पहले दिया गया था।उन्हें हिरासत के आधार दिए गए थे, लेकिन उन दस्तावेजों के आधार पर नहीं जो उन पर निर्भर थे।निर्णय से यह प्रतीत नहीं होता है कि क्या कथित प्रतिवादी के संबंध में कोफेपोसा की धारा 12-ए के तहत घोषणा की गई थी, हालांकि इस तथ्य से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी नजरबंदी 23 मार्च, 1977 तक जारी रही थी।उपरोक्त परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने कहा कि यह प्रतिवादी के लिए खुला है-हिरासत के आदेश की वैधता पर सवाल उठाने के लिए जब उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है

सेफेमा की धारा 6 और 7।एच 38 के तर्क से सहमत होना संभव नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस सी आर।

निर्णय का ए।इस मुद्दे को देखने के दो तरीके हैं।यदि यह निरोध का एक सामान्य आदेश है [धारा 12-ए द्वारा शासित नहीं है और न ही अनुच्छेद 359 (1) के तहत अनुच्छेद 22 के प्रवर्तन को निलंबित करने वाले आदेश द्वारा संरक्षित है] और यदि बंदी अपनी स्वतंत्रता से वंचित होने पर इसे चुनौती नहीं देता है, या इसे असफल रूप से चुनौती देता है, तो कोई कारण नहीं है कि जब उसके खिलाफ SAFEMA के तहत कार्रवाई की जाती है तो उसे इसे चुनौती देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सेफेमा के तहत कार्रवाई हिरासत के तथ्य पर स्वचालित नहीं है, बल्कि केवल प्रारंभिक बिंदु है।दूसरी ओर, यदि यह धारा 12-ए (या अनुच्छेद 359 (1) के तहत अनुच्छेद 22 को निलंबित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश) द्वारा शासित निरोध का आदेश है, तो शायद इसे आपातकाल की अवधि के दौरान भी उन आधारों पर चुनौती दी जा सकती है जो उक्त प्रावधानों द्वारा वर्जित नहीं हैं। दूसरा, यहां तक कि सी यदि सेफेमा के तहत कार्रवाई किए जाने पर इस तरह के आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी जाती है, तो चुनौती उन आधारों तक ही सीमित होनी चाहिए जो आपातकाल की अवधि के दौरान खुले या उपलब्ध थे; अन्यथा अनुच्छेद 358 (1) और अनुच्छेद 359 (1 ए) में समापन शब्दों के पीछे कोई अर्थ नहीं होगा।इसलिए, हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जिसने आपातकाल के दौरान हिरासत के इस तरह के आदेश को चुनौती देने का विकल्प नहीं चुना जब उसे हिरासत में लिया गया था, या

डी.

इसे असफल रूप से चुनौती दी गई, इसे चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब इसे उस पर SAFEMA लागू करने का आधार बनाने की मांग की जाती है।ऊपर वर्णित दो स्थितियों में से किसी एक में, यानी, क्या चुनौती हिरासत की अवधि के

दौरान दी जाती है या बाद में जब SAFEMA के तहत कार्यवाही की जाती है।उनके खिलाफ लिए जाने पर, चुनौती के आधार और न्यायिक जांच ई का दायरा समान होगा।जब उसे हिरासत में लिया गया था तो सीधे हिरासत को चुनौती देने में विफलता, उसे हिरासत की समाप्ति के बाद इसे चुनौती देने से रोकती है, जहां इसे SAFEMA के तहत कार्रवाई शुरू करने का आधार बनाया गया है।हमारे ध्यान में लाया गया दूसरा मामला भारत संघ बनाम में है।मनोहर

एफ लाल नारंग, [1987] 2 एस. सी. सी. 241, खालिद और ओज़ा, जे. जे. की पीठ द्वारा दिया गया निर्णय।इस मामले के तथ्य काफी हद तक शामिल हैं।उत्तरदाता, मनोहर लाल नारंग और एक राम लाल नारंग भाई थे।राम लाल नारंग के खिलाफ 19 दिसंबर, 1974 को कोफेपोसा की धारा 3 (1) के तहत हिरासत का आदेश दिया गया था।उन्होंने 1975 की रिट याचिका संख्या 10 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी, जिसकी अनुमति 30 अप्रैल को दी गई थी।

जी.

1975 और निरोध का आदेश रद्द कर दिया गया।भारत संघ ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में स्थगन के लिए एक आवेदन के साथ एक अपील को प्राथमिकता दी।1 मई, 1975 को इस न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन राम लाल नारंग के आंदोलन पर कुछ शर्तें लगा दीं (बाद में, उक्त अपील को गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था)।25 जून, 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा के बाद, एक अटॉर्नी जनरल।

भारत के लिए वी. ए. राजेंद्र (जे. ई. वी. ए. एन. रेड्डी)।जे.] 1 जुलाई, 1975 को राम लाल के खिलाफ उन्हीं तथ्यों और आधारों पर हिरासत का नया आदेश दिया गया था, जिन आधारों पर उन्हें पहले हिरासत में लिया गया था।निरोध के उक्त आदेश को राम लाल के एक रिश्तेदार द्वारा दायर 1975 की रिट याचिका संख्या 115 में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन 25 नवंबर, 1975 को खारिज कर दिया गया था।उक्त आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में 1977 की अपील सं. 399 में एक अपील दायर की गई थी।इस स्तर पर, राम लाल के खिलाफ सेफेमा की धारा बी 6 और 7 के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिस पर उन्होंने 1975 की रिट याचिका संख्या 720 में दिल्ली उच्च न्यायालय में सवाल उठाया था।जबकि उक्त रिट याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित थी, इस न्यायालय में लंबित 1975 की अपील संख्या 399 सुनवाई के लिए आई और यह कहते हुए इसका निपटारा कर दिया गया कि राम लाल के लिए 1975 की रिट याचिका संख्या 720 में उपलब्ध ऐसी सभी दलीलें उठाने का अधिकार होगा, इस तथ्य के बावजूद कि वे याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित थीं।

1975 की रिट याचिका संख्या 115 (जिससे 1975 की उक्त अपील संख्या 399 उत्पन्न हुई) में आधार उठाए गए थे।1975 की रिट याचिका संख्या 720 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुना गया और खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ राम लाल ने 1982 की एस. एल. पी. संख्या 9361 दायर की, जिसमें अनुमति दी गई थी और अपील को 1985 की C.A.2790 के रूप में गिना गया था, जिसे उक्त डी निर्णय की तारीख पर लंबित कहा गया था।कोफेपोसा की धारा 3 के तहत हिरासत का आदेश था

प्रतिवादी मनोहर लाल नारंग के खिलाफ भी 31 जनवरी, 1975 को मुकदमा चलाया गया।उस समय वे इंग्लैंड में थे।उन्हें भारत लाया गया और हिरासत में ले लिया गया।उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय में 1975 के W.P.2752 के माध्यम से इसे चुनौती दी, जिसकी अनुमति दी गई और 8 जुलाई, 1980 को नजरबंदी को रद्द कर दिया गया।उक्त आदेश के खिलाफ इस न्यायालय में दायर एक अपील ई को भी खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, मनोहर लाल नारंग को इस आधार पर कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया कि वह राम लाल नारंग का भाई (रिश्तेदार) है, जिसे कोफेपोसा की धारा 3 (1) के तहत हिरासत में लिया गया था।यह याद किया जा सकता है कि 1 जुलाई, 1975 के आदेश के तहत राम लाल की नजरबंदी पर सवाल उठाने वाली एक रिट याचिका (जाहिर है, हिरासत का एक आदेश जिस पर कोफेपोसा की धारा 12 (ए) लागू होती है) को दिल्ली उच्च न्यायालय (1975 का डब्ल्यू. पी. संख्या 115) द्वारा खारिज कर दिया गया था और यहां तक कि 1975 की रिट याचिका संख्या 720 (जिसमें उन्हें अपनी नजरबंदी के खिलाफ सभी उपलब्ध आधार उठाने की अनुमति दी गई थी) को भी खारिज कर दिया गया था। ऊपर बताए गए तथ्यों से यह स्पष्ट है कि मनोहर लाल नारंग के खिलाफ सेफेमा के तहत कार्रवाई का आधार आपातकाल की अवधि के दौरान उनके भाई राम लाल जी की नजरबंदी थी, जिसे कोफेपोसा की धारा 12 (ए) द्वारा नियंत्रित किया गया था।यहाँ पहले बताई गई हमारी राय के अनुसार, इस तरह का आदेश SAFEMA के तहत कार्रवाई करने का आधार बन सकता है।जहाँ तक उक्त निर्णय के तर्क का संबंध है, यह प्रभाव है कि निरोध के इस तरह के आदेश की वैधता प्रश्न-एच 40 हो सकती है।

बंदी या उसके रिश्तेदार द्वारा कहा गया है कि जब और जब इस तरह के आदेश को SAFEMA के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आधार बनाया जाना चाहिए।उस आधार पर, अदालत ने राम लाल की नजरबंदी के आदेश की वैधता की जांच करने

के लिए आगे बढ़कर पाया कि उक्त आदेश कुछ अत्यधिक प्रासंगिक और भौतिक परिस्थितियों में मन को लागू न करने के लिए बुरा है।हालाँकि, हमें यह कहना होगा कि हिरासत के आदेश की वैधता जिसके लिए

लागू की गई सी. ओ. एफ. ई. पी. ओ. एस. ए. की धारा 12-ए की जाँच अभी तक आपातकाल के दौरान भी कानून की कसौटी पर की जा सकती थी जैसा कि उसने अनुच्छेद 359 (1) के तहत राष्ट्रपति के आदेश के संचालन के दौरान प्राप्त किया था-इस आधार पर कहें कि धारा 12-ए के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था, या अन्य आधारों पर, जैसा कि उक्त अवधि के दौरान वर्जित नहीं किया गया था।लेकिन एक व्यक्ति सी जो निरोध के आदेश को चुनौती दे सकता था और फिर भी ऐसा नहीं करना चाहता था, उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब निरोध के इस तरह के आदेश को उस पर सेफेमा लागू करने का आधार बनाया जाता है-यह इस कारण से है कि भले ही उसे उक्त आदेश को चुनौती देने की अनुमति दी जाती है जब उसे सेफेमा की धारा 6 के तहत नोटिस दिया जाता है, चुनौती की जांच की जानी चाहिए

कानून की स्थिति का संदर्भ जैसा कि उक्त आदेश के समय प्राप्त हो रहा था

डी.

जिस अवधि के दौरान निरोध का उक्त आदेश लागू था, उस अवधि के दौरान कानून बनाया गया और लागू किया गया।आदेश को चुनौती देने वाले लेकिन अपनी चुनौती में विफल रहने वाले व्यक्ति के मामले में भी यही स्थिति होगी।यहां तक कि कोफेपोसा के तहत हिरासत के सामान्य आदेश के मामले में भी स्थिति समान होगी।एक व्यक्ति जिसने हिरासत के आदेश को (या तो स्वयं या अपने ई अगले मित्र के माध्यम से) चुनौती नहीं दी या इसे चुनौती नहीं दी, लेकिन विफल रहा, उसे सैफेमा के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर हिरासत के आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रश्न 4:सेफेमा की धारा 3 (1) के खंड एफ (सी) में अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की परिभाषा निस्संदेह काफी व्यापक है।इसका अर्थ है और इसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी ऐसी आय, आय या संपत्ति से या उसके माध्यम से अर्जित की गई हो जो किसी ऐसी गतिविधि से प्राप्त की गई हो या उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो किसी ऐसे मामले से संबंधित है जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है।खंड (ग) के उपखंड (ii), (iii) और (iv) इसके दायरे को और व्यापक और विस्तृत करते हैं।इस प्रकार यह परिभाषा न केवल अधिनियम के बाद अर्जित संपत्ति को बल्कि अधिनियम से पहले अर्जित संपत्ति को भी लेती है, चाहे वह कितनी भी लंबी हो।दूसरा, यह ऐसी संपत्ति लेता है जो अवैध गतिविधि से आंशिक रूप से अर्जित की गई हो सकती है, जिस मामले में, एच निश्चित रूप से, धारा 9 में प्रावधान आकर्षित होगा।अवैध गतिविधि अटॉर्नी जनरल नहीं है।

जी.

भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.] 41 धारा 2 में उल्लिखित कानूनों के उल्लंघन तक ही सीमित है, लेकिन वे सभी कानून जो संसद को बनाने की शक्ति है।उदाहरण के लिए, यदि किसी तस्कर ने कर कानूनों से बचकर या चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य लागू कानून (जिसे बनाने की संसद को शक्ति है) द्वारा निषिद्ध कोई अन्य अवैध गतिविधि करके कुछ संपत्ति अर्जित की है, तो वह सब जब्त किया जा सकता है।बी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि यह संसद द्वारा अत्यधिक और अनुचित प्रतिक्रिया का मामला है।तर्क यह है कि यह अधिनियम दंडात्मक प्रकृति का है और "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" की परिभाषा के अनुसार अपने जाल को फैलाना इसे अनुच्छेद 14,19 और 21 के साथ टकराव में लाता है।वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि उक्त परिभाषा अनुपलब्ध है

9 वीं अनुसूची में इसे शामिल करने के कारण, परिभाषा को पढ़ा जा सकता है ताकि इसे केवल सेफेमा की धारा 2 (ए) में उल्लिखित अधिनियमों में निहित निषेधों का उल्लंघन करके अर्जित संपत्तियों तक ही सीमित रखा जा सके।हम इनमें से किसी भी प्रस्तुति को प्रभावी बनाना संभव नहीं पाते हैं।दोनों अधिनियमों को नौवीं अनुसूची में रखे जाने के कारण, उन्हें अनुच्छेद 31 (बी) द्वारा प्रदत्त उन्मुक्ति प्राप्त है।हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि डी याचिकाकर्ता अपनी इस दलील को साबित नहीं कर पाए हैं कि 39 वां (संशोधन) अधिनियम और 40 वां (संशोधन) अधिनियम, जो उक्त अधिनियम को 9 वीं अनुसूची में रखते हैं, असंवैधानिक हैं।उक्त राय के कारणों को यहाँ फिर से दोहराना आवश्यक नहीं है।मामले के इस दृष्टिकोण में, ई अनुचितता, मनमानेपन या उस मामले के लिए भाग-III से संबंधित किसी भी आधार पर उक्त परिभाषा की वैधता पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है।अनुच्छेद 31 (बी) के संरक्षण के अलावा, हम इस कथन में कोई सार नहीं देखते हैं कि परिभाषा मनमाना या भेदभावपूर्ण है और न ही हम उक्त को पढ़ने का कोई कारण देखते हैं।

धारा एफ में निर्दिष्ट कृत्यों के उल्लंघन के लिए इसे सीमित करने की परिभाषा

2 (2) (क) सेफेमा का।हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि लगे हुए व्यक्ति

तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर में ऐसी गतिविधि या इसकी आय या उससे अर्जित परिसंपत्तियों के संबंध में नियमित और उचित खाते नहीं रखे जाते हैं।यदि ऐसा व्यक्ति अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त होता है, तो स्थिति अलग नहीं होगी।विदेशी मुद्रा कानूनों और निर्यात और आयात से संबंधित कानूनों के उल्लंघन में अनिवार्य रूप से कर कानूनों का उल्लंघन शामिल है।वास्तव में, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पिछले कुछ दशकों में तस्करी,

विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, कर चोरी, मादक पदार्थ और अपराध सभी मिश्रित हो गए हैं।करों की चोरी इस तरह की गतिविधि का अभिन्न अंग है।किसी भी प्राधिकरण के लिए किसी भी खाते या अन्य प्रासंगिक के अभाव में यह कहना मुश्किल होगा।

$

सामग्री जो एक तस्कर द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों में से कौन सी एच 42

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. ए. या उनमें से कौन से हिस्से तस्करी और विदेशी विनिमय उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार हैं और कौन सी संपत्तियां या उनके कौन से हिस्से हैं

अन्य कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार (जिसे बनाने की शक्ति संसद के पास है)।यह शायद इसी कारण से है कि यह साबित करने का बोझ है कि कारण बताएँ नोटिस में निर्दिष्ट संपत्तियों का अवैध रूप से अधिग्रहण नहीं किया गया है

बी संपत्तियाँ संबंधित व्यक्ति पर रखी जाती हैं।हो सकता है कि यह एक ऐसा मामला हो जहाँ एक खतरनाक बीमारी के लिए एक कट्टरपंथी उपचार की आवश्यकता होती है।कड़वी दवा बुरी दवा नहीं है।कानून में यह कहना संभव नहीं है कि परिभाषा मनमाना है या अनुचित रूप से व्यापक शब्दों में है।इसके अलावा, धारा 3 के खंड (सी) में प्रयुक्त स्पष्ट और असंदिग्ध भाषा को देखते हुए, पढ़ने के साधन का सहारा लेना संभव या अनुमेय नहीं है।द.

ग

उक्त उपकरण का उपयोग आमतौर पर किसी प्रावधान को असंवैधानिक, अक्षम और अधिकार से बाहर घोषित होने से बचाने के लिए किया जाता है।इसलिए, हमारी राय है कि न तो उक्त परिभाषा की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है और न ही खंड में स्पष्ट और स्पष्ट शब्दों को पढ़ने के लिए कोई वारंट है।जहाँ तक इस तरह के प्रावधान डी के औचित्य का संबंध है, वहाँ पर्याप्त और अधिक है।आखिरकार, इन सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को लोगों और राज्य की कीमत पर अवैध और भ्रष्ट तरीकों से अर्जित और अर्जित किया जाता है।राज्य इस हद तक अपने वैध राजस्व से वंचित है।इन संपत्तियों को न्यायसंगत रूप से वापस जाना चाहिए जहां वे राज्य से संबंधित हैं।हम जो कह रहे हैं वह कोई नई या विधर्मी बात नहीं है।ई हांगकांग बनाम के लिए अटॉर्नी जनरल में प्रिवी काउंसिल के हाल के फैसले के तथ्यों और अनुपात को देखें।रीड [1993] 3 डब्ल्यू. एल. आर. 1143। रेस्पॉन डेंट, रीड, हांगकांग में एक क्राउन-प्रॉसिक्यूटर था।उन्होंने कुछ आपराधिक मुकदमों को दबाने के लिए प्रलोभन के रूप में रिश्वत ली और उनके साथ

धन, न्यूजीलैंड में अर्जित संपत्तियाँ, जिनमें से दो उनके और उनकी पत्नी के नाम पर और तीसरा उनके वकील के नाम पर रखा गया था।

च

उसे रिश्वत लेने के अपराध का दोषी पाया गया और एक आपराधिक अदालत ने उसे सजा सुनाई।हांगकांग प्रशासन ने दावा किया कि न्यूजीलैंड में उक्त संपत्तियों को उसके मालिकों द्वारा क्राउन के लिए रचनात्मक न्यासियों के रूप में रखा गया था और इसे क्राउन को सौंप दिया जाना चाहिए।प्रिवी काउंसिल ने न्यूजीलैंड कोर्ट ऑफ अपील्स के फैसले पर इस दावे को बरकरार रखा।जी लॉर्ड टेम्पलमैन ने न्यायिक समिति की राय देते हुए अपने निष्कर्ष को इस सरल आधार पर आधारित किया कि कर्तव्य के उल्लंघन के माध्यम से एक न्यासी द्वारा प्राप्त कोई भी लाभ लाभार्थी के लिए इक्विटी में है।यह माना जाता है कि एक प्रत्ययी पद पर किसी व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य के उल्लंघन के लिए प्रोत्साहन के रूप में स्वीकार किया गया उपहार एक रिश्वत था और, हालांकि कानून में यह एच प्रत्ययी का था, इक्विटी में वह न केवल रिश्वत की राशि के लिए देनदार बन गया।

' एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए "।ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.) 43

उस व्यक्ति को जिसके लिए शुल्क का स्वामित्व था, लेकिन उसने रिश्वत भी ली थी और उस व्यक्ति के लिए रचनात्मक न्यास पर उसके साथ अर्जित कोई भी संपत्ति।यह भी अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि मूल्यह्रास की गई रिश्वत का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति का मूल्य न्यासी को घायल व्यक्ति को उस मूल्य और रिश्वत की प्रारंभिक राशि के बीच के अंतर का भुगतान करना पड़ता है, और यदि संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो न्यासी अतिरिक्त राशि को बनाए रखने का हकदार नहीं था क्योंकि बी इक्विटी उसे अपने कर्तव्य के उल्लंघन से कोई लाभ अर्जित करने की अनुमति नहीं देती थी।तदनुसार, यह माना जाता है कि इस हद तक कि वे पहले प्रतिवादी द्वारा प्राप्त रिश्वत का प्रतिनिधित्व करते थे, न्यूजीलैंड की संपत्तियों को क्राउन के लिए ट्रस्ट में रखा गया था, और क्राउन का उसमें न्यायसंगत हित था।विद्वान लॉ लॉर्ड ने आगे कहा कि यदि रचनात्मक ट्रस्ट सी के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है और उपलब्ध होने पर संपत्तियों को बाधित किया जाता है, तो संपत्तियों को बेचा जा सकता है और आय को कुछ शांगरी ला में ले जाया जा सकता है जो रिश्वत और अन्य भ्रष्ट धन को क्रमांकित बैंक खातों में छुपाता है।कोई भी व्यक्ति उन बैंकरों की अनैतिकता को समझ सकता है जो क्रमांकित खाते रखते थे, लेकिन सरकारों और उनके कानूनों की अनैतिकता को कम करना मुश्किल है जो ऐसी डी प्रथाओं को मंजूरी देते हैं-वास्तव में उन्हें प्रोत्साहित करते हैं।इस निर्णय का अनुपात समान रूप से लागू होता है जहां कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करके और राज्य और उसके राजस्व के नुकसान के लिए संपत्ति अर्जित करता है, जहां एक अधिनियम इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए प्रदान करता है, भले ही रीड में निर्दिष्ट प्रत्ययी संबंध मौजूद न हो। यह देखा जा सकता है कि रीड में प्रयुक्त ई अवधारणा एक सामान्य कानून अवधारणा थी, जबकि यहाँ इस तरह के ज़ब्त के लिए प्रदान किए गए एक स्पष्ट वैधानिक प्रावधान का मामला है।हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि "समाज के हित व्यक्तिगत हितों के लिए सर्वोपरि हैं और दोनों को न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण संबंध में लाया जाना चाहिए।यदि प्रगति को अतीत की तरह भविष्य का नियम बनाना है, तो केवल संपत्ति व्यवसाय मानव जाति की अंतिम नियति नहीं है।(लुईस हेनरी मॉर्गनः प्राचीन समाज)।

{

प्रश्न संख्या 5:याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि SAFEMA के प्रावधानों का विस्तार रिश्तेदारों, सहयोगियों और

जी 1

अन्य 'धारक' फिर से अति-पहुँच या अति-चौड़ाई का मामला है, जैसा कि इसे कहा जा सकता है-अत्यधिक विनियमन का मामला।यह प्रस्तुत किया जाता है कि सेफेमा की धारा 2 (2) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आने वाले किसी व्यक्ति के रिश्तेदारों या सहयोगियों ने अपनी संपत्तियों का अधिग्रहण किया हो सकता है, वे अवैध माध्यमों से हो सकते हैं, लेकिन कोई कारण नहीं है कि उन संपत्तियों को सेफेमा के तहत जब्त किया जाए क्योंकि वे एच से संबंधित हैं या उनके सहयोगी हैं।

एक बंदी या दोषी, जैसा भी मामला हो।यह इंगित किया गया है कि स्पष्टीकरण (2) में 'रिश्तेदार' और स्पष्टीकरण (3) में 'सहयोगी' की परिभाषा इतनी व्यापक है कि किसी व्यक्ति को दूर से संबंधित या उससे जुड़े व्यक्ति के रूप में भी लाया जा सकता है।

दोषी/बंदी, सेफेमा के जाल के भीतर, और एक बार जब वह जाल के भीतर आ जाता है, तो उसकी सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को अधिनियम के तहत जब्त किया जा सकता है।हमारी राय में, उक्त तर्क एक गलत धारणा पर आधारित है।

सेफेमा को धारा 2 (2) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आने वाले व्यक्ति की "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" को जब्त करने के लिए निर्देशित किया जाता है।रिश्तेदारों और सहयोगियों को केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया जाता है कि दोषी या बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति, उनके नाम पर अर्जित या रखी गई संपत्ति, अधिनियम के जाल से न बचे।यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति अर्जित संपत्तियों की जांच करते हैं।

[

अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर ऐसी अवैध गतिविधि से।कभी-कभी वे स्वामित्व और स्वामित्व को हस्तांतरित करने के इरादे से ऐसी संपत्तियों को उन्हें हस्तांतरित करते हैं।वास्तव में, यह मायने नहीं रखता कि ऐसा रिश्तेदार या सहयोगी दोषी/बंदी

की संपत्तियों को कैसे रखता है-चाहे वह बेनामी के रूप में हो या केवल एक नाम-ऋणदाता के रूप में या मूल्य के लिए या किसी भी मामले में एक प्रामाणिक हस्तांतरणकर्ता के रूप में।

च

डी.

दूसरे तरीके से।वह उन संपत्तियों पर दावा नहीं कर सकता है और उसे अधिनियम के तहत उन्हें राज्य को सौंप देना चाहिए।चूँकि वह एक रिश्तेदार या सहयोगी है, जैसा कि अधिनियम द्वारा परिभाषित किया गया है, वह यह साबित होने के बाद कोई बचाव नहीं कर सकता है कि उस संपत्ति का अधिग्रहण बंदी द्वारा किया गया था-चाहे वह उसके अपने नाम पर हो या उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम पर।यह धारा 2 (2) के खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा अपनाए गए या अपनाए जा सकने वाले कई उपकरणों ई का प्रतिकार करने के लिए है कि उक्त उप-धारा के खंड (सी) और (डी) में उल्लिखित उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों को भी अधिनियम के दायरे में लाया जाता है।उनके स्वामित्व या कॉन की संपत्तियों के स्वामित्व का तथ्य

विक्ट/डिटेन्यू दोषी/डिटेन्यू और उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों के बीच संबंध प्रस्तुत करता है।केवल दोषी/बंदी की संपत्तियों की मांग की जाती है।

च

ज़ब्त किए जाने के लिए, वे जहाँ भी हों।विचार यह है कि उसकी संपत्तियों तक पहुँचाया जाए जिनके नाम पर उन्हें रखा गया है या जिनके द्वारा उन्हें रखा गया है।रिश्तेदारों और दोस्तों की स्वतंत्र संपत्तियां, जो दोषी/बंदी के लिए पता लगाने योग्य नहीं हैं, को जब्त करने की मांग नहीं की जाती है और न ही वे SAFEMA * के दायरे में हैं।हम जो कहते हैं उसे समझाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।खंड

जी.

यह कि अधिनियम का उद्देश्य यही था, प्रस्तावना के पैरा 4 से स्पष्ट है जिसमें कहा गया हैःऔर जबकि ऐसे व्यक्तियों ने कई मामलों में अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और विश्वासपात्रों के नाम पर इस तरह के लाभ के बावजूद अपने द्वारा अर्जित संपत्तियों को धारण किया है।हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है या अधिनियम के दायरे को सीमित किया जा सकता है, हम केवल अधिनियम के उद्देश्य का पता लगाने और पुनः आश्वासन देने के लिए इसका उल्लेख कर रहे हैं।

एच.

हम स्वयं यह समझते हैं कि हमारे द्वारा किया गया निर्माण उक्त वस्तु के अनुरूप है।

45

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. वी. रेड्डी, जे.]

(ग) खंड (क) या खंड (ख) क में निर्दिष्ट व्यक्ति के किसी रिश्तेदार की बात करता है।

(जो एक दोषी या एक बंदी की बात करता है)।इसी तरह, खंड (घ) ऐसे दोषी या बंदी के सहयोगियों के बारे में बात करता है।यदि हम स्पष्टीकरण (3) को देखें जो निर्दिष्ट करता है कि खंड (घ) में निर्दिष्ट सहयोगी कौन हैं, तो मामला अधिक स्पष्ट हो जाता है। एसोसिएट्स का अर्थ हैः((i) कोई भी व्यक्ति जो ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसरों (आउटहाउस सहित) में रह रहा था या रह रहा है B ['ऐसा व्यक्ति' खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट दोषी या बंदी को संदर्भित करता है; (ii) कोई भी व्यक्ति जो मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा है या ऐसे दोषी/बंदी के खाते रख रहा है; (iii) व्यक्तियों का कोई संघ, व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी जिसमें ऐसा दोषी/बंदी सदस्य, भागीदार था।

या निदेशक; (iv) कोई भी व्यक्ति जो खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी का सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है, किसी भी समय जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संघ का सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है।

व्यक्ति, व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी; (v) कोई भी व्यक्ति जो खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा था या खाते रख रहा था; (vi) किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी जहां (ए) ऐसे दोषी/बंदी द्वारा ट्रस्ट बनाया गया है; या (बी) ऐसे दोषी/बंदी द्वारा ट्रस्ट में योगदान की गई संपत्ति का मूल्य।

राशि, योगदान की तारीख को, मूल्य के 20 प्रतिशत से कम नहीं

ई.

उस तारीख को न्यासों की परिसंपत्तियाँ; और (vii) जहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यह मानता है कि ऐसे दोषी/बंदी की कोई भी संपत्ति उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति, ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा रखी गई है।इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि जोड़ने वाली कड़ी या सांठगांठ, जैसा कि इसे कहा जा सकता है, दोषी/बंदी एफ की संपत्ति या संपत्ति का स्वामित्व है।

या ऐसे बंदी/दोषी का पता लगाया जा सकता है।इस संदर्भ में धारा 4 भी उतनी ही प्रासंगिक है।यह घोषणा करता है कि "इस अधिनियम के प्रारंभ से, किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अपने द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखना विधिसम्मत नहीं होगा।"ऐसी सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है।इस धारा की भाषा अधिनियम के दायरे का संकेत है।धारा जी में खंड (सी) और (डी)

2 (2) और उसमें होने वाले स्पष्टीकरण (2) और (3) का अर्थ अधिनियमन की समग्र योजना और उद्देश्य के आलोक में लगाया और समझा जाना चाहिए।विचार यह है कि दोषी/बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, भले ही ऐसी संपत्तियां किसी रिश्तेदार या एच 46 के नाम पर रखी गई हों या रखी गई हों।

उक्त दो स्पष्टीकरणों में परिभाषित एक सहयोगी।विचार यह नहीं है कि ऐसे रिश्तेदारों या सहयोगियों की स्वतंत्र संपत्तियों को जब्त किया जाए, जिन्हें उन्होंने अवैध रूप से अर्जित किया हो, बल्कि केवल धोखाधड़ी करने वालों की संपत्तियों तक पहुंचने के लिए।

उन संपत्तियों के संबंध में सभी लेन-देनों को नजरअंदाज करते हुए, जहां भी वे हैं, वहां उसके लिए विक्ट/डिटेन्यू या ट्रेस करने योग्य संपत्तियां।उदाहरण के रूप में, बी एक ऐसे मामले को लेता है जहां एक दोषी/बंदी अपने रिश्तेदार या सहयोगी के नाम पर एक संपत्ति खरीदता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वह ऐसा व्यक्ति केवल एक नाम-ऋणदाता बनना चाहता है या क्या वह वास्तव में चाहता है कि ऐसा व्यक्ति उसका वास्तविक मालिक और/या स्वामी होगा-या उपहार देता है या अन्यथा अपनी संपत्तियों को अपने किसी रिश्तेदार या सहयोगी के पक्ष में स्थानांतरित करता है।

सहयोगी, या उन्हें अपने किसी रिश्तेदार या सहयोगी को बेचने का इरादा रखता है -

एस.

ऐसे सभी मामलों में, सभी कथित लेन-देनों को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा, जब तक कि दोषी/बंदी या उसका रिश्तेदार/सहयोगी, जैसा भी मामला हो, यह स्थापित नहीं करता है कि ऐसी संपत्ति या संपत्तियां अवैध रूप से नहीं हैं।

अर्जित संपत्तियाँ "धारा 3 (सी) के अर्थ के भीतर।मामले के इस दृष्टिकोण में, इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि स्वतंत्र रूप से

डी ऐसे रिश्तेदारों और सहयोगियों की अर्जित संपत्तियों को भी जब्त कर लिया जाएगा, भले ही वे किसी भी तरह से दोषी/बंदी से जुड़े न हों।जहाँ तक धारा 2 (2) (ई) में उल्लिखित धारकों (रिश्तेदार और सहयोगी नहीं होने) का संबंध है, उनके साथ एक अलग आधार पर व्यवहार किया जाता है।यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित करता है कि वह विचार के लिए सद्भावना से हस्तांतरणकर्ता है, तो उसकी ई संपत्ति भले ही किसी दोषी/बंदी से खरीदी गई हो-जब्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।यह दोहराना भी उतना ही आवश्यक है कि यह स्थापित करने का भार कि धारा 6 के तहत जारी कारण दर्शाओ नोटिस में उल्लिखित संपत्तियां, और जो उस तारीख को दोषी/बंदी के किसी रिश्तेदार या सहयोगी द्वारा रखी गई हैं, दोषी/बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां नहीं हैं, ऐसे रिश्तेदार/सहयोगी पर निर्भर करता है।उसे स्थापित करना चाहिए।

च

कि उक्त संपत्ति बंदी/दोषी द्वारा प्रदान किए गए धन या संपत्ति के साथ अर्जित नहीं की गई है या कि वे वास्तव में ऐसे बंदी/दोषी से संबंधित नहीं हैं या नहीं हैं।हमें नहीं लगता कि संसद का कभी यह कहने का इरादा था कि सभी रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्तियों को अवैध रूप से अधिग्रहित किया जा सकता है, केवल इसलिए जब्त किया जाएगा क्योंकि वे दोषी/बंदी के जी रिश्तेदार

या सहयोगी हैं।उन संपत्तियों और दोषी/बंदी के बीच संबंध होना चाहिए, जिसे गलत साबित करने का बोझ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिश्तेदार/सहयोगी पर है।मामले के इस दृष्टिकोण में, इस ओर से याचिकाकर्ताओं की आशंका और तर्क को गलत आधार पर आधारित माना जाना चाहिए।एच रिश्तेदारों और सहयोगियों या ई में उल्लिखित व्यक्तियों को लाता है

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए "।इस प्रकार धारा 2 (2) का खंड (ई) अनुच्छेद 31-बी के संरक्षण के अलावा न तो भेदभावपूर्ण है और न ही अक्षम ए है।

प्रश्न संख्या 6:याचिकाकर्ताओं ने कोफेपोसा की धारा 5-ए की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि यह दोहरे सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करती है

अनुच्छेद 22 के खंड (5) द्वारा प्रदान किया गया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त खंड बी

बंदी को दो अधिकार देता है।, ((i) जिनके आधार पर

:

निरोध का आदेश उसे जल्द से जल्द सूचित करने पर आधारित है और (ii) निरोध के आदेश के खिलाफ प्रतिनिधित्व करने का जल्द से जल्द अवसर दिया जाए-बॉम्बे राज्य बनाम देखें।आत्मा राम वैद्य, [1951] एस. सी. आर. 167.यदि आधारों में अप्रासंगिक या गैर-मौजूद आधार शामिल हैं, तो यह प्रस्तुत किया जाता है, पहले अधिकार का उल्लंघन किया जाता है और यदि आधारों में अस्पष्ट सी आधार शामिल हैं, तो दूसरे अधिकार का उल्लंघन किया जाता है।विद्वान वकील के अनुसार, अनुच्छेद 22 (5), जैसा कि पिछले चार दशकों से अधिक समय से इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है, का अर्थ हैःनिवारक निरोध का आदेश प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर आधारित होता है और जहां ऐसी संतुष्टि इस आधार पर हुई है कि जिनमें से कुछ प्रासंगिक और निश्चित आधार हैं और कुछ अप्रासंगिक, अस्पष्ट और गैर-मौजूद हैं, तो न्यायालय के लिए यह अनुमान लगाना संभव या अनुमेय नहीं है कि किन आधारों ने उसकी संतुष्टि के गठन को प्रभावित किया है-जिसका अर्थ है कि निरोध का आदेश प्राधिकरण की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करता है।

यदि अनुच्छेद 22 (5) का यही अर्थ है और कहता है, तो संसद के लिए यह कहते हुए कानून बनाने का अधिकार नहीं है कि जहां जिन आधारों पर अपेक्षित संतुष्टि बनाई गई है, वे आंशिक रूप से अच्छे और आंशिक रूप से खराब हैं, फिर भी ई आदेश को अच्छे आधारों के संदर्भ में और उनके आधार पर अच्छा माना जाना चाहिए, खराब आधारों को छोड़कर।प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसा कानून अनुच्छेद 22 (5) के सीधे विरोध में होगा।आइए हम इस उपसमुच्चय की जांच करें

सायन काफी करीब से।

कोफेपोसा की धारा 5-ए को तैयार एफ के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है।

संदर्भ।इसमें लिखा हैः

" 5 - ए.पृथक्करण योग्य आधार निरोध-जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत निरोध के आदेश के अनुसरण में हिरासत में लिया गया है, जो दो या दो से अधिक आधारों पर किया गया है, तो निरोध का ऐसा आदेश बनाया गया माना जाएगा।

ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग-अलग और तदनुसार

(क) ऐसा आदेश केवल इसलिए अमान्य या अप्रभावी नहीं समझा जाएगा क्योंकि एक या कुछ आधार हैं या हैं

((i) अस्पष्ट,

एच>

((ii) गैर-मौजूद

क.

((ग) अप्रासंगिक,

((iv) ऐसे व्यक्ति से न तो जुड़ा हुआ है और न ही निकटता से जुड़ा हुआ है, या

(v) किसी भी अन्य कारण से अमान्य,

और इसलिए यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि ऐसा आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी को धारा 3 की उप-धारा (1) के संदर्भ में संतुष्ट किया गया होगा।

एस.

शेष जमीन या मैदान और निरोध का आदेश दिया;

(ख) निरोध का आदेश देने वाली सरकार या अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने उप-धारा (1) के तहत निरोध का आदेश दिया है।

डी.

शेष आधारों या आधारों के संदर्भ में वह उप-धारा।

खंड दो भागों में है।पहले भाग में कहा गया है कि जहां दो या दो से अधिक आधारों पर निरोध का आदेश दिया जाता है, "निरोध ई का ऐसा आदेश ऐसे प्रत्येक आधार पर अलग-अलग किया गया माना जाएगा"।जबकि दूसरे भाग में कहा गया है कि इस तरह के आदेश को केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं माना जाएगा कि एक या कुछ आधार या तो अस्पष्ट, अस्तित्वहीन, अप्रासंगिक या असंबद्ध हैं।यह कि दूसरा भाग केवल पहले भाग की निरंतरता और परिणामी है, संबंधित शब्दों "और तदनुसार" से स्पष्ट होता है।दूसरा भाग आगे जाता है।

च

और कहता है कि हिरासत का आदेश शेष अच्छे आधार या आधारों से संतुष्ट होने पर किया गया माना जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो।दोनों भाग "और" शब्द से जुड़े हुए हैं।

अब, यह विवाद से परे है कि निरोध का आदेश एक ही आधार पर जी पर आधारित हो सकता है।इस न्यायालय के कई फैसलों में कहा गया है कि एक भी पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य को व्यक्ति को हिरासत में रखने के लिए आवश्यक संतुष्टि बनाने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है।देबू महतो बनाम।पश्चिम बंगाल राज्य, [1974] 4 एस. सी. सी. 135 में यह देखा गया कि सामान्य तौर पर एक अधिनियम अपेक्षित संतुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है और किसी भी मामले में एक अधिनियम पर्याप्त हो सकता है।वह एच वैगन तोड़ने का मामला था और अधिनियम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास [जे. ई. वी. एन. रेड्डी।जे.] 49 को अभिनिर्धारित किया गया कि एक अधिनियम पर्याप्त है।ए अनिल डे बनाम में भी इसी सिद्धांत को दोहराया गया था।पश्चिम बंगाल राज्य, [1974] 4 एससीसी 514।यह रेलवे सिग्नल सामग्री की चोरी का मामला था।यहाँ भी एक अधिनियम को पर्याप्त माना गया था।

इसी तरह, इजरायल एस. के. वी. में।पश्चिम दिनाजपुर के जिला मजिस्ट्रेट और अन्य।[1975] 3 एस. सी. सी. 292 और धारुआ कानू बनाम।पश्चिम बंगाल राज्य, [1975] 3 एस. सी. सी. 527, बड़ी मात्रा में टेलीग्राफ तांबे के तारों की चोरी और हटाने का एकल कार्य

क्रम को बनाए रखने के लिए क्रमशः रेलवे मछली प्लेटों को पर्याप्त रखा गया था

हिरासत में लेना।सरस्वती शेषगिरी बनाम।केरल राज्य और अन्र।, [1982] 2 एस. सी. सी. 310, एकल अधिनियम, कोफेपोसा के तहत उत्पन्न होने वाला मामला।, भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा का निर्यात करने का प्रयास पर्याप्त था।संक्षेप में, सिद्धांत ऐसा प्रतीत होता है, हालांकि आम तौर पर एक अधिनियम नहीं माना जा सकता है।

निरोध के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त, एक अधिनियम सी निरोध के आदेश को बनाए रख सकता है यदि अधिनियम ऐसी प्रकृति का है जो यह इंगित करता है कि यह संगठित गतिविधि की अभिव्यक्ति का एक संगठित कार्य है।अधिनियम की गंभीरता और प्रकृति भी प्रासंगिक है।परीक्षण यह है कि क्या यह कार्य ऐसा है कि यह एक निष्कर्ष को जन्म देता है कि व्यक्ति इसी तरह के प्रीजुडी में लिप्त रहना जारी रखेगा।

सियाल गतिविधि।यही कारण है कि वैगन के एकल कार्य-तोड़ना, डी की चोरी

सिग्नल सामग्री, बड़ी मात्रा में टेलीग्राफ तांबे के तारों की चोरी और रेलवे मछली प्लेटों को हटाने के लिए पर्याप्त रूप से रखा गया था।इसी तरह, जहां व्यक्ति ने योजनाबद्ध और पूर्व-नियोजित तरीके से किसी विदेशी देश को भारी मात्रा में भारतीय मुद्रा का निर्यात करने का प्रयास किया, तो यह माना गया कि इस तरह का एक ही कार्य इस निष्कर्ष की गारंटी देता है कि वह भविष्य में अपनी गतिविधि को दोहराएगा और इसके अलावा, उसे इस तरह की पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि में लिप्त होने से रोकने के लिए उसकी नजरबंदी आवश्यक है।यदि कोई उन कृत्यों को देखता है जिन्हें कोफेपोसा को रोकने के लिए बनाया गया है, तो वे सभी या तो तस्करी के कार्य हैं या विदेशी मुद्रा में हेरफेर के।ये कृत्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जो अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं और अक्सर इस तरह की गतिविधि के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होते हैं।इन कृत्यों से पहले अच्छी मात्रा में योजना और संगठन किया जाता है।

;

यह।वे सामान्य कानून और व्यवस्था के अपराधों की तरह नहीं हैं।हालाँकि, यदि किसी भी मामले में एक ही कार्य निरोध के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं पाया जाता है, जिसे अच्छी तरह से रद्द किया जा सकता है, लेकिन इसे एक सिद्धांत के रूप में नहीं कहा जा सकता है कि एक ही कार्य निरोध के लिए आधार नहीं बन सकता है।जिस पर

इसके विपरीत, यह करता है।दूसरे शब्दों में, यह आवश्यक नहीं है कि किसी आदेश को हिरासत में रखने या बनाए रखने के लिए आधारों में भिन्नता होनी चाहिए।जी.

अब, एक मामला लें, जहाँ कोफेपोसा के तहत एक ही व्यक्ति के खिलाफ हिरासत के तीन आदेश दिए जाते हैं।प्रत्येक आदेश केवल एक आधार पर आधारित होता है जिसकी आपूर्ति बंदी को की जाती है।यह पाया गया है कि ऐसे दो आदेशों के समर्थन में हिरासत का आधार या तो अस्पष्ट है या अप्रासंगिक है।लेकिन तीसरे क्रम के समर्थन में आधार प्रासंगिक है, निश्चित एच 50

ए और समीपस्थ।ऐसे मामले में, जबकि पहले दो आदेशों को रद्द कर दिया जाएगा, तीसरा आदेश कायम रहेगा।धारा 5-ए का पहला भाग (मुख्य भाग) ठीक यही करना चाहता है।जहां निरोध का आदेश एक से अधिक आधारों पर आधारित है, वहां धारा एक कानूनी कल्पना का निर्माण करती है, अर्थात।, यह माना जाना चाहिए कि हिरासत के उतने ही आदेश हैं जितने आधार हैं जिसका अर्थ है कि ऐसे प्रत्येक आदेश एक स्वतंत्र आदेश है।इसका परिणाम

यह वही है जो हमारे द्वारा ऊपर दिए गए चित्रण में है।इसका दूसरा भाग केवल स्पष्टीकरणात्मक और व्याख्यात्मक है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि यह "तदनुसार" शब्द से शुरू होता है-इस तथ्य के अलावा कि यह पहले भाग में "और" शब्द से जुड़ा हुआ है।ऐसी स्थिति में, हम यह देखने में असमर्थ हैं कि धारा को अनुच्छेद 22 (5) के साथ असंगत सी के रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है।यदि पहला भाग नहीं होता और धारा में केवल दूसरा भाग होता, तो इस तर्क को समझा जा सकता है कि यह धारा अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत आती है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है-वास्तव में के. याडिगिरी रेड्डी बनाम में यही स्थिति थी।पुलिस आयुक्त आई. एल. आर. 1972 ए. पी. 1025 जैसा कि हम वर्तमान में इंगित करेंगे।अनुच्छेद 22 (5) और प्रथम डी-धारा 5-ए के मुख्य भाग के बीच किसी भी विसंगति या संघर्ष की कल्पना करना मुश्किल है।संसद एक कानूनी कल्पना बनाने के लिए सक्षम है और उसने इस मामले में ऐसा किया।अनुच्छेद 22 (5) अलग-अलग आधारों पर एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक साथ एक से अधिक आदेश देने पर प्रतिबंध नहीं लगाता है।ऐसा कहते हुए कोई निर्णय हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है।चाहे जो भी हो, हम यह नहीं समझते कि संसद ई एक कानूनी कल्पना तैयार करके यह कहने में सक्षम क्यों नहीं है कि

जहां एक से अधिक आधारों पर निरोध का आदेश दिया जाता है, यह माना जाना चाहिए कि हिरासत के उतने ही आदेश हैं जितने आधार हैं।यदि कानूनी कल्पना का यह निर्माण सक्षम है, तो धारा और अनुच्छेद 22 (5) के बीच किसी भी विसंगति का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है।

आर

च

यह सच है कि धारा 5-ए-या उस मामले के लिए, धारा की वैधता

5 - राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 का ए, जो समान शब्दों में है-इस न्यायालय में अब तक सवाल नहीं उठाया गया है, हालांकि इसे कई फैसलों में लागू किया गया है।रिपोर्ट किए गए निर्णयों में से तीन हमारे ध्यान में लाए गए हैं।, गुजरात राज्य बनाम। चमन लाल मंझीभाई सोनी [1981] 2 एस. सी. सी. 24, प्रकाश चंद्र मेहता बनाम।आयुक्त और सचिव, केरल

जी.

[1985] पूरक।एस. सी. 144 और एन. मीरा रानी बनामतमिलनाडु राज्य, [1989] 4 एस. सी. सी. 418.वास्तव में, अंतिम उल्लिखित निर्णय में, इसकी वैधता की पुष्टि करने वाली टिप्पणियां हैं, हालांकि इस पर कोई अंतिम राय व्यक्त नहीं की गई है।

सवाल क्योंकि उस मामले में इसका प्रचार नहीं किया गया था।यह भी हमारे संज्ञान में लाया गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय की एक पीठ ने कोफेपोसा के तहत उत्पन्न होने वाले मामले में एच उक्त प्रावधान की पुष्टि की है और इसे लागू किया है।

आई एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.) 51 अब, ए. के. याडिगिरी रेड्डी में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय पर आते हुए, ए. पी. निरोध अधिनियम, 1970 की धारा 6 (ए) निम्नानुसार हैः

" कोई भी निरोध आदेश अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा।

यह कारण कि जिन आधारों पर आदेश दिया गया है, उनमें से एक या अधिक अस्पष्ट या अप्रासंगिक हैं, जब दूसरा आधार या आधार बी ऐसी किसी जानकारी से ग्रस्त नहीं है या पीड़ित नहीं है।

इस प्रकार आंध्र प्रदेश के प्रावधान में एक प्रावधान एपी था।

धारा 5-क के दूसरे भाग के निकट लेकिन इसमें धारा के पहले (मुख्य) भाग के अनुरूप या अनुमानित कोई प्रावधान नहीं था।

धारा 5-ए।यह धारा 5-ए का पहला भाग है जो काल्पनिक कल्पना का निर्माण करता है; दूसरा भाग केवल पहले भाग में कानूनी कल्पना के प्रभाव और परिणाम को विस्तृत रूप से बताता है।दूसरा भाग, यदि यह अकेला खड़ा होता, तो शायद इसे अनुच्छेद 22 (5) के अंतर्गत होने के रूप में वर्णित किया जा सकता था, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा समझा और समझा गया था-और यही आंध्र है।

प्रदेश उच्च न्यायालय कहता है-लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है जैसा कि ऊपर डी में समझाया गया है।अतः उक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं के मामले को किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ाता है।यह कहने के बाद, हमें लागू विभिन्न निरोध कानूनों के तहत निरोध की शक्ति के प्रयोग के संबंध में न्यायमूर्ति गजेंद्रगडकर की चेतावनी को दोहराना चाहिए।जी. सदनादन बनाम में संविधान पीठ के लिए बोलते हुए।केरल राज्य, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. ई

1925 , विद्वान न्यायाधीश ने टिप्पणी कीः "हम इस विचार से अशिष्ट रूप से परेशान महसूस करते हैं कि कई अधिकारियों को नियमों द्वारा प्रदत्त बहुत व्यापक शक्तियों का निरंतर प्रयोग उक्त अधिकारियों की अंतरात्मा को संविधान की सर्वोच्च आवश्यकता के प्रति असंवेदनशील बना सकता है, यदि कुंद नहीं है, तो आपातकाल के दौरान भी, भारतीय नागरिकों की स्वतंत्रता को नियमों द्वारा निर्दिष्ट औचित्यपूर्ण आवश्यकता के अस्तित्व के बिना नहीं लिया जा सकता है।इन मामलों के साथ कुछ हद तक आकस्मिक और बेपरवाह तरीके से व्यवहार करने की प्रवृत्ति जो संभवतः इस तरह के निर्बाध उपयोग के निरंतर उपयोग का परिणाम है।

च

शक्तियाँ, अंततः जी पर बुनियादी मूल्यों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं जो इस देश में जीवन के लोकतांत्रिक तरीके की स्थापना है।

स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में, हिरासत की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों की ओर से अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।

एक अतिरिक्त प्रश्नःयाचिकाकर्ताओं में से एक एच की ओर से पेश हुए डॉ. घटते

संविधान 44 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा निम्नलिखित प्रभाव के लिए एक दिलचस्प निवेदन करते हुए, संसद ने अपनी घटक शक्ति में कार्य करते हुए, अनुच्छेद 22 के खंड (4) के साथ-साथ खंड (7) को प्रतिस्थापित किया है और इसे केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है कि वह उस तारीख को निर्दिष्ट करे जिससे उक्त संशोधन लागू होगा।(संशोधन) अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) केंद्र सरकार को आने के लिए अलग-अलग तिथियां तय करने का अधिकार देती है।

उक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करना।हालांकि केंद्र सरकार ने संशोधन अधिनियम के कई अन्य प्रावधानों के संबंध में लागू होने की तारीख निर्दिष्ट की है, लेकिन उसने उस तारीख को निर्दिष्ट करने के लिए नहीं चुना है जिससे अनुच्छेद 22 के खंड (4) और (7) के प्रतिस्थापन में संशोधन लागू होंगे।44 वां (संशोधन) अधिनियम अप्रैल, 1979 में लागू किया गया था और भले ही चौदह साल से अधिक समय बीत चुका हो, केंद्र सरकार ने उक्त संशोधनों को लागू करना उचित नहीं समझा है।केंद्र सरकार की ओर से इस विफलता का प्रभाव उक्त संशोधनों को लगभग रद्द करने का है।उक्त संशोधनों को लागू करते समय, संसद कभी भी इस बात पर विचार नहीं कर सकती थी कि केंद्र सरकार उन पर और अधिक विचार करेगी

डी चौदह वर्ष से अधिक।केंद्र सरकार को संशोधन अधिनियम की भावना के अनुसार कार्य करना चाहिए।इसे उचित रूप से कार्य करना चाहिए।यह केवल उस तारीख को निर्दिष्ट करने से इनकार करके संविधान संशोधन को पूर्ववत नहीं कर सकता है जिससे यह लागू होगा।भले ही केंद्रीय सरकार को दी गई शक्ति को एक सशर्त कानून के रूप में चिह्नित किया जाता है, फिर भी तथ्य यह रहेगा कि ऐसी शक्ति का भी उचित रूप से और उचित समय के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए।क्या केंद्र सरकार कुछ और वर्षों तक इंतजार कर सकती है और क्या अदालत केंद्र सरकार को आदेश देने में असमर्थ होगी

उक्त संशोधन को लागू करें?यदि ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि संसद ने वर्ष 1979 में संविधान में संशोधन किया था, उस पीढ़ी के लिए नहीं बल्कि अगली पीढ़ी के लिए?44 वें (संशोधन) अधिनियम की धारा एफ 1 (2) वास्तव में आवश्यक घटक शक्ति के त्याग या प्रत्यर्पण का एक उदाहरण है और इसलिए, खराब है।वकील का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और ऐसा होने नहीं दिया जा सकता है; केंद्र सरकार को संवैधानिक संशोधन के साथ खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए-एक संशोधन जो विशेष रूप से अनुच्छेद 22 के खंड (4) में निहित सुरक्षा को मजबूत करता है।

जी.

हालाँकि, हम इन मामलों के उद्देश्यों के लिए डॉ. घाटते के निवेदन पर कोई राय व्यक्त करना आवश्यक नहीं समझते हैं, क्योंकि उनके तर्क की स्वीकृति-यह मानते हुए कि हम करते हैं, इन याचिकाओं के परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।हम पहले ही यह मान चुके हैं कि कोफेपोसा की धारा 3 के तहत एच को हिरासत में रखने के आदेश दिए गए थे।

एटॉर्नी जनरल।भारत के लिए v.ए. प्रजीवंदास (जे. ई. वी. एन. रेड्डी, जे.) 53 धारा 12-ए अभी भी सेफेमा की धारा 2 (2) (बी) के साथ पठित धारा 2 (1) के अर्थ के भीतर और ए के उद्देश्य के लिए निरोध के आदेशों का प्रतिनिधित्व करता है।अगर हम यह भी मान लें कि 44 वें (संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रभावी खंड (4) और (7) में संशोधन उस दिन से लागू हो गए हैं जिस दिन संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी, तो भी परिणाम अलग नहीं होगा।मामले के इस दृष्टिकोण में, ए. के. रॉय बनाम के आधार पर प्रत्यर्थी के निवेदन पर कोई राय बी व्यक्त करना भी आवश्यक नहीं है।भारत संघ,

[1982] 2 एस. सी. आर. 272, अर्थात।, क्या उक्त निर्णय में राय हो सकती है

चौदह वर्ष बीतने के बाद भी वैध रूप से लागू किया गया।

संक्षेप में:

एस.

(1) संसद दोनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से सक्षम थी

कोफेपोसा और सेफेमा।

क.

(2) इस निर्णय के मुख्य भाग में दिए गए कारणों के लिए, हम भारत के संविधान के 38 वें और 40 वें संशोधन अधिनियमों की वैधता पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं, जिसमें कोफेपोसा और सेफेमा को 9 वीं डी अनुसूची में रखा गया है।हम उन्हें अच्छा और वैध मानते हैं।संविधान के 42 वें संशोधन अधिनियम की वैधता के संबंध में भी कोई तर्क नहीं दिया गया है।

(3 क) कोफेपोसा की धारा 3 के तहत किया गया निरोध का आदेश,

जो धारा 12-ए द्वारा शासित थी, वह अभी भी एस. ए. एफ. ई. एम. ए. की धारा 2 (2) (बी) के उद्देश्य के लिए और उसके अर्थ के भीतर निरोध ई का आदेश है।चूँकि राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 14,21 और 22 को निलंबित करने वाले अनुच्छेद 359 (1) के तहत एक आदेश जारी किया था, इसलिए यह संसद के लिए अनुच्छेद 359 के खंड (1 ए) के आधार पर कोफेपोसा की धारा 12-ए को उस अवधि के लिए अधिनियमित करने के लिए सक्षम हो गया, जिसके लिए राष्ट्रपति का आदेश लागू था।इसका उद्देश्य आपातकाल के उद्देश्यों को प्राप्त करना था।एक बार जब धारा 12-ए को कानून का एक सक्षम टुकड़ा माना जाता है, तो उसके तहत किए गए निरोध के आदेश (यानी, निरोध के आदेश जिन पर उक्त प्रावधान लागू होता है) को SAFEMA की धारा 2 (2) (बी) के उद्देश्य के लिए और उसके अर्थ के भीतर निरोध के आदेशों के बराबर नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से धारा 2 (2) (बी) की स्पष्ट भाषा (जिसमें जी परंतुक (iii) भी शामिल है)-और संविधान की नौवीं अनुसूची में उन्हें शामिल करने के आधार पर दोनों अधिनियमों द्वारा प्राप्त संरक्षण को देखते हुए।

...

च

(ख) निरोध का आदेश जिसके लिए धारा 12-क लागू होती है और साथ ही निरोध का आदेश जिसके लिए धारा 12-क लागू नहीं थी, ऐसे निरोध पर सेफेमा लागू करने के लिए आधार के रूप में काम कर सकता है और एच 54

सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [1994] एस. यू. पी.1 एस. सी. आर. ए. ने अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को बशर्ते कि निरोध का ऐसा आदेश धारा 2 (2) (बी) के परंतुक में किसी भी उपखंड को आकर्षित नहीं करता है।यदि इस तरह के बंदी ने उक्त नजरबंदी पर सवाल उठाने का विकल्प नहीं चुना (या तो खुद से)

या अपने अगले मित्र के माध्यम से) उस अवधि के दौरान जब निरोध का ऐसा आदेश लागू था,-या उस पर हमला करने में असफल रहा है-वह, या उसके रिश्तेदार और सहयोगी इसकी वैधता पर हमला या सवाल नहीं उठा सकते हैं जब बी उसे या उसके रिश्तेदारों के लिए SAFEMA लागू करने का आधार बनाया जाता है या

सहयोगी।(4) सेफेमा की धारा 3 के खंड (सी) में "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" की परिभाषा अमान्य या अप्रभावी नहीं है।

ग

(5) रिश्तेदारों और सहयोगियों के लिए SAFEMA का आवेदन [in

धारा 2 (2) के खंड (ग) और (घ) समान रूप से वैध और प्रभावी हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को इस अधिकार के दायरे में लाने का उद्देश्य और उद्देश्य समान रूप से वैध है।

सेफेमा बंदी या दोषी की संपत्तियों तक पहुँचना है, जैसा भी मामला हो, वे जहाँ भी हों, चाहे उन्हें कैसे भी रखा गया हो और जिनके द्वारा भी उन्हें रखा गया हो।उनकी कल्पना स्वतंत्र को खोने की दृष्टि से नहीं की गई है।

डी.

इस निर्णय में बताए गए ऐसे रिश्तेदारों और सहयोगियों की संपत्तियां।धारा 2 (2) के खंड (ई) द्वारा निपटाए गए 'धारकों' की स्थिति अलग है जैसा कि निर्णय के मुख्य भाग में समझाया गया है।

(6) कोफेपोसा की धारा 5-ए अमान्य या अमान्य नहीं है।ई अनुच्छेद 22 के खंड (5) का उल्लंघन नहीं करता है।

(7) याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहे हैं कि सेफेमा का कोई भी प्रावधान अनुच्छेद 14,19 या 21 का उल्लंघन करता है-संविधान की नौवीं अनुसूची में अधिनियम को शामिल करने के कारण उन्हें मिलने वाले संरक्षण के अलावा।

च

सभी रिट याचिकाओं, स्थानांतरित मामलों और अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है।अदालत और अधिकारी जिनके समक्ष सेफेमा के तहत कार्यवाही लंबित है, वे कानून के अनुसार और इस फैसले के आलोक में उनका निपटारा करने के लिए आगे बढ़ेंगे।यह सभी संबंधित लोगों के हित में है कि कार्यवाही को पूरी जानबूझकर गति के साथ समाप्त किया जाए।

जी.

1981 की सिविल अपील सं. 1418 को वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया।

टी. पी. में 1993 की आई. ए. संख्या 1 पर कोई आदेश नहीं माँगा जाता है। (ग) 1978 का सं. 17।

मामलों का निपटारा किया गया।

एजी.